स्वदेशी पत्रिका

वर्ष–22, अंक–4, चैत्र–वैशाख 2071, अप्रैल 2014

संपादक

विक्रम उपाध्याय

कार्यालय

धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग
रामकृष्णपुरम्, नयी
दिल्ली–110022
से प्रकाशित
दूरभाष : 011–26184595
स्वदेशी जागरण समिति की ओर से ईश्वर दास महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

आवरण कथा – पृष्ठ–6

अमरीका, यूरोप और जापान आने वाले समय में अपने व्यावसायिक हितों को लेकर मोदी के साथ संबंध सुधारने में लगे हैं तो दूसरी ओर शत्रु राष्ट्र तमाम घटनाक्रमों पर नजर गड़ाए दिखाई देते हैं। ऐसे में दुनियाभर में अपनी दादागिरी के लिए प्रसिद्ध अमरीका का नरेन्द्र मोदी के प्रति अपना व्यवहार बदलने की बात पर कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए।

कवर पेज

अ नु क्र म

आवरण कथा :
उम्मीदे नई केन्द्र सरकार से
– डॉ. अश्विनी महाजन /6

कृषि :
कृषि पर बढ़ रहा दबाव
– अरविन्द जयतिलक /8

कृषक :
अच्छी नहीं, किसानों की इतनी अपेक्षा
– आशीष कुमार 'अंशु' /10

समीक्षाः
किसानों की राजनीतिक ताकत
– देविन्दर शर्मा /12

लोकतंत्रः
कैसा सांसद चुनेंगे आप?
– निरंकार सिंह /14

हलचलः
ईमान की कसौटी पर होगी अगली सरकार
– आलोक पुराणिक /16

पर्यटनः
बेडु पाको बारमासा
– विमल भाई /19

विचार–विमर्शः
पानी बचाना है तो बिजली बचाइए
– अरुण तिवारी /21

स्वास्थ्यः
कब रुकेगी कैंसर एक्सप्रेस
– अखिलेश अखिल /23

समस्याः
युवा पीढ़ी न बह जाए इस सैलाब में
– भारत डोगरा /25

बाजारवादः
हमारे बाजारों पर चीन का बढ़ता वर्चस्व
– जयंतीलाल भंडारी /27

भ्रष्टाचारः काले धन पर बेबस केन्द्र सरकार
– बलवीर पुंज /29

संस्कृति :
भारतीय काल गणना की सार्वभौमिकता व खगोल शुद्धता
– डॉ. भगवती प्रकाश /31

पाठकनामा/4, समाचार परिक्रमा/35

पाठकनामा

चुनाव जीतने वाली पार्टी निभाए अपना वायदा

16वीं लोकसभा चुनाव शुरू हो गया है। सभी पार्टियां मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए चुनावी घोषणा पत्रों के द्वारा रिझाने में लगे हुए हैं। एक पार्टी भ्रष्टाचार, महंगाई–बेरोजगारी दूर करने की बात करती है तो एक पार्टी मुफ्त दवा और मुफ्त शिक्षा का वायदा करती है तो एक पार्टी अपने को ईमानदार साबित करती है। भले ही आज घोषणापत्र में सभी पार्टियों ने जो वायदे किए है अगर जीतने पर कोई भी एक पार्टी अपने घोषणा पत्र को ईमानदारी से अमल करें तो निश्चय ही भारत आने वाले दिनों में विकास की नई ऊंचाई को छुएगा।

– मनोज कुमार, आर.के. पुरम्, नई दिल्ली

शिक्षा और किसानों की फिर अनदेखी

आज हर पार्टी चुनावी दौर में हर प्रकार का वायदा निभाने का जनता से कर रही है परन्तु कृषि प्रधान देश में किसानों की दशा दिन प्रति दिन खराब होती जा रही है। खास कर छोटे किसानों की दुर्दशा काफी खराब है। उनके पास खेती के लायक जमीन भी कम है और खेती के लिए खाद भी नहीं। अगर किसानों की यही दुर्दशा रही तो एक दिन देश में अनाज का भण्डार भी खत्म हो जाएगा। मनुष्य को सबसे पहले अपने खाना का इंतजाम करना चाहिए फिर जरूरी चीजें होती हैं। लेकिन आधुनिक युग में मानव मशीनी युग बन गया है। जहां मेहनतकश व्यक्ति को दो रोटी जुटे के लिए दिन रात एक कर देने पड़ते हैं वहीं पढ़े लिखे व्यक्ति को दो रोटी आराम से मिल जाती है। एक समय कृषि को प्रथम व्यवसाय माना जाता था लेकिन अब इसे गरीबी की जननी मानते है। हमें नहीं भूलना चाहिए अगर किसान नहीं होंगे तो हमें अनाज कौन देगा? आज देश में जिस तरह महंगाई बढ़ रही हैं उसका कारण है ज्यादातर छोटे किसानों द्वारा खेती छोड़ना। आज बिहार, उत्तराखण्ड, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के ज्यादातर लोग शहरों में काम कर रहे हैं। उन्होंने अपना पुश्तैनी धंधा खेतीबाड़ी छोड़ दिया है। चुनाव के बाद बनने वाली नई सरकार को चाहिए कि वह किसानों के बच्चों को ऐसी शिक्षा दें जिससे आने वाली पीढ़ी को खेती के लिए खुद जैविक बीजों का संरक्षण करना और कम से कम रसायनिक खाद का उपयोग करना पड़े तभी देश की अनेक समस्याएं खुद खत्म हो जाएगी।

– चित्रा सिंह डुमोलिया, हरियाणा

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

''धर्मक्षेत्र'' शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेल : swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 150 रुपए

आजीवन सदस्यता शुल्क: 15,00 रुपए

यदि शुल्क भेजने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

या आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740

IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram)

उन्होंने कहा

इतिहास में यह पहली बार हो रहा है कि चुनाव से पहले ही प्रधानमंत्री अपने लिए नए घर की तलाश में जुट गए हैं। चुनाव के बाद किसकी सरकार सत्ता में आएगी इस पर अब किसी को शक नहीं।

– लालकृष्ण आडवाणी

मोदी विकास पुरुष हैं। उन्हें धर्म, क्षेत्र और समुदाय से ऊपर समर्थन मिल रहा है।

– चंद्रबाबू नायडू

लोगों के मतदान में बढ–चढ़कर हिस्सा लेने से नक्सली बौखला गए हैं। नक्सलियों की ये घटनाएं उनकी बौखलाहट और घिनौनी मानसिकता का परिचायक है।

– रमन सिंह

भ्रष्टाचार देश के लिए दैत्य से कम नहीं है। भ्रष्टाचार हिन्दुस्तान में एक सच्चाई है। अगर आपको भ्रष्टाचार से लड़ना है तो बातचीत बंद करके एक्शन लेना होगा।

– राहुल गांधी

भाजपा सभी धर्मों व जाति का सम्मान करती है। संप्रग सरकार ने देश को घोटालों और महंगाई के अलावा देश को कुछ नहीं दिया। आज आर्थिक भ्रष्टाचार चरम पर है और प्रधानमंत्री खामोश हैं।

– राजनाथ सिंह

लोकतंत्र स्वीमिंग पुल की तरह होता है। अगर आप इसका पानी समय–समय पर नहीं बदते तो यह गंदा हो जाता है। इसी प्रकार जनता को अब केन्द्र सरकार बदलनी चाहिए।

– राम जेठमलानी

राजनीतिक पार्टियों ने फिर दिखाए किसानों को सपने

नई सरकार बनने में कुछ ही समय रह गया हैं। सरकार चाहे किसी की भी बनें। आज कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चुनाव के दौरान में सभी राजनीतिक पार्टियों ने पूरा जोर डाला है और यह वायदा भी किया है कि उनकी सरकार के बनते ही इन मुद्दों पर गंभीरता से काम किया जाएगा। चाहे मुद्दे गरीबी हटाने के हों, भ्रष्टाचार मिटाने के हों इत्यादि। मसलन सभी दल द्वारा गरीब और मध्य आय वर्ग के लोगों को तत्काल राहत पहंचाने के हैं और सबसे ऊपर किसानों को दयनीय हालात में तुरंत सुधार लाने का है। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में कृषि और किसान के लिए काफी कुछ कहा गया है। गौरतलब है कि कांग्रेस को छोड़ बाकी सभी राजनीतिक दलों ने जीएम खाद्य फसलों के ट्रायल के विरोध में अपना मत व्यक्त किया है। भारतीय जनता पार्टी ने उससे आगे बढ़कर यह कहा है कि जीएम खाद्य फसलों को तब तक अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक उसके मनुष्य, जीवों और वनस्पति पर दुष्प्रभाव न होने की पुष्ट हो जाए। कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में खुदरा व्यापार क्षेत्र में विदेशी निवेश की मंजूरी को किसानों के लिए वरदान माना है। कांग्रेस का सपना है कि कृषि और उससे जुड़े क्षेत्र में निजी क्षेत्र का निवेश हो। यानी कृषि का निगमीकरण हो जाए। बाकी उन्हीं चीजों को फिर से लिख दिया गया है जो पहले से ही घोषणापत्र में रहा है। मसलन सिंचित क्षेत्र का आकार बढ़ाया जाएगा। किसानों को सस्ता कर्ज दिया जाएगा और न्यूनतम समर्थन मूल्य भी लागत के आधार पर बढ़ाया जाएगा। कांग्रेस के लिए साठ साल से किसानों की मर्ज एक ही है और उनका समाधान भी वह डिस्प्रीन की गोली से ही करना चाहती है। अलबत्ता कांग्रेस किसानों और गरीबों के लिए पहले की तरह ही आंसू इस बार भी अपने घोषणापत्र में बहा रही है। कांग्रेस के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि आखिर क्यों किसान आत्महत्या कर रहे हैं। क्योंकि युवा पीढ़ी किसानी छोड़ कर भाग रही है। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार किसानों को मुनाफे का हिस्सेदार बनाने का वायदा किया है। भाजपा ने किसानों को कर्ज देने के साथ–साथ कृषि क्षेत्र में भारी सरकारी निवेश का भी भरोसा दिलाया है। इसके अलावा अधिक उत्पादकता वाले बीज और सस्ते कृषि तकनीक को भी उपलब्ध कराने का भाजपा ने दम भरा है। तीसरे मोर्चे के कथित अगुआ समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव के लिए कहने को किसान और कामगार प्रमुख मुद्दे तो हैं, पर उनका जोर वोट बैक आधारित राजनीति पर हैं। उनके लिए किसानों को योजनाओं में प्राथमिकता से ज्यादा नौकरियों में मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात पर है। एक और दल जनता दल यूनाइटेड की बात करें तो वह भी कहते हैं कि किसानों की भलाई के लिए काम करना जरूरी है, पर उनका वोट बैंक प्रवासी मजदूर हैं इसलिए जदयू के नेताओं ने इसी मुद्दे को आगे बढ़ाया। यह अजीब विरोधाभाष है कि लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों के चुनावी वायदे के केंद्र में रह कर भी किसान आज विकास और प्राथमिकताओं के हाशिये पर खडे हैं। यह सुन कर और सोंच कर शर्मिंदगी महसूस होती है कि हमारी कुछ जनसंख्या का आधे से भी अधिक कृषि कार्य करने वाले लोग दो जून की रोटी नहीं कमा पाते। उनको साल भर का रोजगार नहीं मिलता। अपनी जरूरतों के लिए उन्हें अपने बच्चों तक को बेचना पड़ता है और जब सब तरफ से निराशा मिलती है तो उन्हें आत्महत्या करने पर भी मजबूर होना पड़ता है। एक तरफ अमरीका में प्रति किसान औसत सालाना आमदनी 60 हजार डॉलर है वहीं भारत में औसत कमाई 60 हजार रुपये भी नहीं है। जहां विकसित देशों में किसानों को नई तकनीक, कंप्यूटर, इंटरनेट और सभी मशीनरी उपलब्ध है वहां भारत में किसानों के पास मामूली कृषि उपकरण भी नहीं है। यह कहकर संतोष कर सकते है कि इस बार केंद्र में सरकार बनाने वाली पार्टी जरूर किसानों के हितों को प्राथमिकता देगी। देखा जाए तो सभी राजनीतिक दलों के चुनाव घोषणा पत्रों में किसानों के लिए कहा तो बहुत कुछ गया है लेकिन यह कहीं पहले की भांति खोखले वायदे ही न हो इसका डर लगता है। जरूरत इस बात की है कि जो भी दल सत्ता में आए वो किसानों और कृषि के उत्थान के लिए सच्चे मन से काम करें ताकि देश में किसानों और खेती की सूरत बदलें।

उम्मीदे नई केन्द्र सरकार से

अमरीका, यूरोप और जापान आने वाले समय में अपने व्यावसायिक हितों को लेकर मोदी के साथ संबंध सुधारने में लगे हैं तो दूसरी ओर शत्रु राष्ट्र तमाम घटनाक्रमों पर नजर गड़ाए दिखाई देते हैं। ऐसे में दुनियाभर में अपनी दादागिरी के लिए प्रसिद्ध अमरीका का नरेन्द्र मोदी के प्रति अपना व्यवहार बदलने की बात पर कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेकिन इन तमाम घटनाक्रमों में मोदी को लेकर अमरीका की विडंबना साफ दिखाई देती है।

■ **डॉ. अश्विनी महाजन**

आम चुनाव के नजदीक आने के साथ ही शेयर बाजार और विदेशी मुद्रा बाजार में नई आशाएं जन्म लेने लगी हैं। रुपए और डॉलर की बाजार विनिमय दर जो अगस्त में 68.84 रुपए पहुंच गई थी, अब 61 रुपए से नीचे आ गई है। यानी पिछले छह महीनों से कम समय में रुपया लगभग 11.5 प्रतिशत सुधर गया है। गौरतलब है कि मार्च 2013 में डॉलर 54.4 रुपए का था और मात्र पांच महीने से भी कम समय में वह 68.84 रुपए का हो गया था। हमारे वित्तमंत्री चिदंबरम कहते हैं कि अमरीका की विस्तारवादी मौद्रिक नीति के चलते लगभग सभी मुल्कों की मुद्रा डॉलर के मुकाबले में कमजोर हुई, लेकिन भारत के संदर्भ में यह पूरा सच नहीं है। शेष विश्व में यह कमजोरी 6 प्रतिशत से 12 प्रतिशत के बीच रही, लेकिन भारत अकेला ऐसा मुल्क था, जहां रुपया डॉलर के मुकाबले 26.5 प्रतिशत तक कमजोर हो गया। इसकी वजह भी है। वर्ष 2012–13 के दौरान देश का व्यापार घाटा जीडीपी के 11 प्रतिशत और भुगतान घाटा जीडीपी के लगभग 5 प्रतिशत तक पहुंच गया। डॉलर के संदर्भ में हमारा घाटा 89 अरब डॉलर था। हमारा विदेशी कर्ज जो मार्च 2010 में 260 अरब डॉलर था, सितंबर 2013 तक आते–आते 400 अरब डॉलर तक पहुंच गया। बढ़ते व्यापार घाटे और भुगतान घाटे की भरपाई के लिए सरकार ने मोटेतौर पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, संस्थागत विदेशी निवेश और अंतरराष्ट्रीय बाजारों से कर्ज उठाने की खुली नीति अपना ली। विदेशी निवेशकों द्वारा सरकार की इस अंधी नीति को भांपते हुए गलत फायदे उठाए जाने लगे। विदेशी कंपनियों ने ट्रांसफर प्राइसिंग के जरिए भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा बाजार भेजनी शुरू कर दी। मारुति, एसीसी जैसी कई कंपनियों ने अचानक अपनी रॉयल्टी की राशि बढ़ा दी और भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा बाजार भेजी जाने लगी। गौरतलब है कि वर्ष 2012–13 में 31.7 अरब डॉलर रॉयल्टी, लाभांश, ब्याज, वेतन इत्यादि के रूप में विदेशी कंपनियों ने अपने देश भेज दिए।

आज हम अपने जीडीपी का लगभग 28 प्रतिशत के बराबर आयात करते हैं जिस पर लगाम लगानी होगी। केवल सोने के आयातों पर प्रतिबंध लगाना काफी

आज हम अपने जीडीपी का लगभग 28 प्रतिशत के बराबर आयात करते हैं जिस पर लगाम लगानी होगी। केवल सोने के आयातों पर प्रतिबंध लगाना काफी नहीं है। हमें टेलीकॉम और पावर प्लांटों के आयातों पर रोक लगानी चाहिए। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और निजी क्षेत्र की लार्सन और टुब्रो सरीखी कंपनियों की ऑर्डर बुक सूख रही है और सरकार विदेशों से पावर प्लांट आयात करने को प्रोत्साहन दे रही है।

नहीं है। हमें टेलीकॉम और पावर प्लांटों के आयातों पर रोक लगानी चाहिए। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और निजी क्षेत्र की लार्सन और टुब्रो सरीखी कंपनियों की ऑर्डर बुक सूख रही है और सरकार विदेशों से पावर प्लांट आयात करने को प्रोत्साहन दे रही है। हमें अपने किसानों को सहारा देना होगा ताकि वे ज्यादा उत्पादन करें और देश में खाने–पीने की चीजों की महंगाई थमे।

इस निराशाजनक स्थिति में हमें नई सरकार से भी अपेक्षा रहेगी कि वह शून्य पर पहुंच चुकी मैन्यूफैक्चरिंग ग्रोथ को रफ्तार देगी।

वर्तमान स्थिति पर एक नजर

भारत में अमरीकी राजदूर नैंसी पॉवेल के अचानक इस्तीफे से पिछले दिनों राजनयिक हलकों में हलचल–सी मच गई। भारत में अमरीकी राजदूर को हटाए जाने की यह पहली घटना नहीं है, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में अमरीकी राजदूत का इस्तीफा सामान्य घटना नहीं मानी जा सकती है। भारत में आम चुनावों के मद्देनजर उभरती परिस्थितियों के अनुरूप नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने के साथ इस इस्तीफे को जोड़कर देखा जा रहा है।

पिछले कुछ महीनों में जब से भाजपा ने नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है, इस मुद्दे को लेकर गरमाहट बढ़ गई है। कथित रूप से भारत के कुछ सांसदों ने अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को पत्र लिखकर मोदी को वीजा न देने की नीति को जारी रखने की बात की थी। वर्तमान में संप्रग नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार भी इस मुद्दे पर अमरीकी नीति को सही नहीं ठहरा सकती।

अमरीकी सरकार हमेशा ही अपनी कंपनियों के व्यावसायिक हितों की रक्षा के लिए प्रयासरत रहती है। इसी क्रम में हाल ही में अमरीकी कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने गुजरात में मोदी से मिलकर उनके साथ संबंधों को बेहतर करने का प्रयास किया। गौरतलब है कि नरेन्द्र मोदी को अमरीकी सरकार ने वीजा देने से मना कर दिया। अमरीका ने अकेले ही यह काम नहीं किया, बल्कि इंग्लैंड ने भी मोदी को वीजा देने से मना करके उसका साथ दिया था, लेकिन अक्टूबर 2012 में ब्रिटेन ने नरेन्द्र मोदी को वीजा देकर इस प्रकरण का अंत कर दिया और ब्रिटेन के उच्चायुक्त को मोदी से मिलने का निर्देश दिया।

ब्रिटिश सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया कि उसके गुजरात के साथ कई हित जुड़े हुए हैं। ब्रिटेन के इस फैसले के बाद अमरीका पर मोदी के बहिष्कार को समाप्त करने के लिए दबाव बढ़ चुका है और अब प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार बनने के बाद अमरीकी सरकार अपने व्यावसायिक हितों के संरक्षण के लिए मोदी के बहिष्कार का अंत करने का रास्ता खोजने लगी है।

फरवरी माह में अमरीकी राजदूत नैंसी पॉवेल ने गुजरात जाकर मोदी से मुलाकात की थी। जो लोग मोदी को विवादास्पद कहते थे, अब मोदी की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। जैसे–जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, दुनिया का रुख मोदी के साथ बदलता जा रहा है। अब वे लोग गुजरात के विकास मॉडल की बात करते हैं। उद्योगों के लिए मोदी द्वारा की जा रही पहल की बात होती है। चाहे वह रतन टाटा के लिए नैनो कारखाना खोलने की बात हो या मारूति सुजुकी के लिए सुविधा देने की बात। अब अमरीकी एजेंसियां यह कह रही हैं कि यदि मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो अमरीका का उन्हें वीजा मना करना बेमानी बात रह जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्हें सभी प्रकार की राजनयिक सुविधाएं प्राप्त होंगी।

हालांकि विदेश नीति के संदर्भ में नरेन्द्र मोदी की सोच सामने नहीं आई है लेकिन इस बात का आभास जरूर है कि चीन जो वर्तमान में भारत की ढुलमुल विदेशी नीति के चलते विस्तारवादी सोच रखता है, उसे अब थमना पड़ेगा। अगर पाकिस्तानी मीडिया और टेलीविजन के कार्यक्रम कोई पैमाना हों तो यह स्पष्ट है कि पाकिस्तान भारत में एक मजबूत नेतृत्व के उभरने के डर से ग्रस्त है। पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियां भी इस बारे में गंभीरतापूर्वक विचार कर रही हैं।

बांग्लादेश से सताए हुए हिन्दू शरणार्थियों की बात हो या पाकिस्तान से आ रहे हिन्दू शरणार्थियों की, नरेन्द्र मोदी स्पष्ट रूप से हिन्दुओं के प्रति दुर्व्यवहार से अपनी अप्रसन्नता जाहिर कर चुके हैं। जबकि अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अकर्मण्यता की नीति की आलोचना करती रही है। उन्हें लगता है कि देश में आतंकवादी गतिविधियों के मद्देनजर मोदी पर पाकिस्तान के खिलाफ सख्त नीति अपनाने का दबाव होगा।

अमरीका, यूरोप और जापान आने वाले समय में अपने व्यावसायिक हितों को लेकर मोदी के साथ संबंध सुधारने में लगे हैं तो दूसरी ओर शत्रु राष्ट्र तमाम घटनाक्रमों पर नजर गड़ाए दिखाई देते हैं। ऐसे में दुनियाभर में अपनी दादागिरी के लिए प्रसिद्ध अमरीका का नरेन्द्र मोदी के प्रति अपना व्यवहार बदलने की बात पर कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेकिन इन तमाम घटनाक्रमों में मोदी को लेकर अमरीका की विडंबना साफ दिखाई देती है। ❑

कृषि क्षेत्र पर बढ़ रहा दबाव

माना जा रहा है कि प्रकृति पर आधारित कृषि, बाढ़ व सूखा जैसी प्राकृतिक आपदा से फसल की क्षति और ऋणों के बोझ के कारण बड़े पैमाने पर किसान खेती छोड़ने को मजबूर हुए हैं। पिछले एक दशक के दौरान महाराष्ट्र में सर्वाधिक 7 लाख 56 हजार, राजस्थान में 4 लाख 78 हजार, असम में 3 लाख 30 हजार और हिमाचल में एक लाख से अधिक किसान खेती को तिलांजलि दे चुके हैं।

■ अरविन्द जयतिलक

सेवा क्षेत्र और उद्योग–धंधों के लगातार विस्तार एवं कृषि योग्य जमीन घटने के बावजूद देश में कृषि पर निर्भरता बढ़ी है। यह खुलासा हाल में प्रकाशित वर्ल्ड वॉच संस्थान की रिपोर्ट से हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 1980 से 2011 के दौरान भारत में कृषि में लगी आबादी में 50 फीसद का इजाफा हुआ है। हालांकि नियंत्रण स्तर पर इस अवधि के दौरान कुल आबादी में कृषि आबादी कम हुई है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि 2011 में विश्व की कृषि में लगी आबादी 37 फीसद थी और यह 1980 की संख्या के मुकाबले 12 फीसद की गिरावट दर्शाता है। हालांकि संख्या के स्तर पर समान अवधि के दौरान यह आबादी 2.2 अरब से बढ़कर 2.6 अरब हो गयी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन की कृषि आबादी में 33 फीसद की वृद्धि हुई है जबकि अमेरिका में यह 37 फीसद कम हुई है। भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था अभी भी कई तरह की समस्याओं से ग्रस्त है। मसलन जहां सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में कृषि का योगदान कम हो रहा है, वहीं खेती से विमुख होने वाले किसानों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में अगर जीवनयापन के स्रेत के रूप में कृषि पर निर्भरता बढ़ती है तो यह भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत नहीं है।

एक आंकड़े के मुताबिक 2001 में देश में 12 करोड़ 73 लाख किसान थे। 2011 में यह संख्या घटकर 11 करोड़ 87 लाख रह गयी है।

माना जा रहा है कि प्रकृति पर आधारित कृषि, बाढ़ व सूखा जैसी प्राकृतिक आपदा से फसल की क्षति और ऋणों के बोझ के कारण बड़े पैमाने पर किसान खेती छोड़ने को मजबूर हुए हैं। पिछले एक दशक के दौरान महाराष्ट्र में सर्वाधिक 7 लाख 56 हजार, राजस्थान में 4 लाख 78 हजार, असम में 3 लाख 30 हजार और हिमाचल में एक लाख से अधिक किसान खेती को तिलांजलि दे चुके हैं। इसी तरह उत्तराखंड, मेघालय, मणिपुर और अरुणाचल जैसे छोटे राज्यों में भी किसानों की संख्या घटी है।

एक आंकड़े के मुताबिक चीन सत्तर हजार किलोमीटर से अधिक हाइवे का निर्माण कर चुका है। लेकिन वहां एक इंच भी कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण नहीं किया है। यही वजह है कि कृषि योग्य भूमि कम होने के बावजूद चीन उत्पादन के मामले में हमसे आगे है। इसमे दो राय नहीं कि इन साढ़े छह दशकों में देश ने चतुर्दिक प्रगति की है। मूलभूत सुविधाओं का विस्तार हुआ है और प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है लेकिन फसलों और बाजारों की दूरी न घटने, फसलों का उचित मूल्य न मिलने, कृषि में मशीनीकरण और आधुनिक तकनीक का अभाव इत्यादि कारणों से कृषि और किसानों की दुर्दशा भी बढ़ी है। बढ़ती ऋणग्रस्तता की वजह से किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं।

आश्चर्यजनक यह है कि इस दौरान देश में कृषि मजदूरों की संख्या बढ़ी है। आंकड़े बताते हैं कि 2001 में जहां 10 लाख 68 हजार कृषि मजदूर थे, 2011 में उनकी संख्या बढ़कर 14 करोड़ 43 लाख हो गयी। इससे इस निष्कर्ष पर पहुंचना गलत नहीं होगा कि खेती करने वाले किसान ही खेतिहर मजदूर बने हैं। इसका मूल कारण खेती के रकबे में लगातार गिरावट, सिंचाई एवं उर्वरक की अनुपलब्धता और बिजली का अभाव इत्यादि है। आंकड़े बताते हैं कि देश में 1990 से 2005 के बीच 20 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि कम हुई है।

गौरतलब है कि एक हजार हेक्टेयर खेती की जमीन कम होने पर 100 किसानों और 760 खेतिहर मजदूरों की आजीविका छिनती है। आज देश में प्रति व्यक्ति कृषि भूमि की उपलब्धता 0.18 हेक्टेयर रह गयी है। 82 फीसद किसान लघु व सीमांत किसानों की श्रेणी में आ गए हैं। उनके पास दो हेक्टेयर या उससे भी कम कृषि भूमि रह गयी है। कृषि की विकास दर लगातार घट रही है। 1950–51 में देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की भागीदारी 51.9 थी, जो 1990–91 में 34.9 फीसद रह गयी। 2012–13 में यह घटकर 13.7 फीसद पर आ गयी है। यह सही है कि उद्योग–धंधे, कल–कारखाने एवं सेवा क्षेत्र में सतत विकास की वजह से कृषि की भागीदारी कम हुई है लेकिन पिछले तीन दशक में कृषि पर निर्भर आबादी में इजाफा दर्शाता है कि गैर–कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का आनुपातिक फैलाव नहीं हुआ है।

दूसरी ओर खेती के विकास में क्षेत्रवार विषमता बढ़ना, प्राकृतिक बाधाओं से पार पाने में विफलता, भूजल का खतरनाक स्तर तक नीचे गिरना और हरित क्रांति वाले इलाकों में पैदावार में कमी और भी चिंताजनक है। आश्चर्य है कि इस दिशा में सुधार की ठोस पहल नहीं हो रही है। लगातार बढ़ती आबादी, शहरों तथा उद्योगों का विस्तार एवं कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण भी कृषि की समस्या बढ़ा रहा है।

देश में स्पेशल इकोनॉमी जोन (सेज) और हाइवे निर्माण के नाम पर लाखों हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि अधिग्रहीत की जा चुकी है। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि देश में उदारीकरण की नीतियां लागू होने के बाद 1990 से लेकर 2005 के बीच लगभग 60 लाख हेक्टेयर खेती की जमीन का अधि ग्रहण किया गया है।

विडंबना यह कि उसका उपयोग गैर–कृषि कार्य में हो रहा है। जिन क्षेत्रों में सरकारें खेती की जमीनों को अधिग्रहीत कर रही है, वहां, विस्थापन की विकट समस्या उत्पन्न हो गयी है। जमीनें गंवाने के बाद किसानों के पास जीविका का कोई साधन नहीं रह गया है। लिहाजा वे खानाबदाशों सा जीवन गुजारने को विवश हैं। विस्थापित किसानों के लिए सरकार के पास न ठोस पुनर्वास नीति है और न रोजी–रोजगार से जोड़ने का कोई कारगर तरीका। नतीजा कल तक जो किसान थे, वे आज खेतिहर मजदूर हैं। यकीनन विकास के लिए भूमि का अधिग्रहण जरूरी है लेकिन कृषि योग्य भूमि का उपयोग बदलना कहां तक उचित है। पड़ोसी देश चीन में भी विकास के निमित्त भूमि का अधिग्रहण किया जाता है।

एक आंकड़े के मुताबिक चीन सत्तर हजार किलोमीटर से अधिक हाइवे का निर्माण कर चुका है। लेकिन वहां एक इंच भी कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण नहीं किया है। यही वजह है कि कृषि योग्य भूमि कम होने के बावजूद चीन उत्पादन के मामले में हमसे आगे है। इसमे दो राय नहीं कि इन साढ़े छह दशकों में देश ने चतुर्दिक प्रगति की है। मूलभूत सुविधाओं का विस्तार हुआ है और प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है लेकिन फसलों और बाजारों की दूरी न घटने, फसलों का उचित मूल्य न मिलने, कृषि में मशीनीकरण और आधुनिक तकनीक का अभाव इत्यादि कारणों से कृषि और किसानों की दुर्दशा भी बढ़ी है। बढ़ती ऋणग्रस्तता की वजह से किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं।

एक आंकड़े के मुताबिक 2004 में 4385, 2005 में 3175 और 2006 में 1901 किसानों ने आत्महत्या की। वैसे यह राहतकारी है कि किसानों की आत्महत्या के आंकड़ों में कमी आ रही है। 2007 में 1627 किसानों ने आत्महत्या की। 2012 में यह संख्या घटकर 697 रह गयी। किसान क्रेडिट कार्ड और फसलों की बीमा योजना से किसानों को राहत मिली है। अच्छी बात है कि सरकार कृषि के विकास में तेजी लाने और इस क्षेत्र में पूंजी निवेश में वृद्धि के लिए प्रयासरत है। उसकी पहल से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन और वितरण, राष्ट्रीय बागवानी मिशन जैसी अनगिनत योजनाएं चल रही हैं और इससे किसानों को लाभ पहुंच रहा है। उचित होगा कि सरकार कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के साथ गैर–कृषि क्षेत्र को भी प्रोत्साहित करे ताकि अधिकाधिक लोगों को रोजगार मिल सके। अन्यथा कृषि पर निर्भर आबादी में इजाफा होगा और यह कोई सुखद तस्वीर नहीं होगी। ❑

अच्छी नहीं, किसानों की इतनी उपेक्षा. . .

किसानों के लिए सिचाई एक महत्वपूर्ण जरूरत होती है, खेती के दौरान। दे□ा की 55 फीसदी खेती योग्य भूमि वर्शा पर निर्भर करती है। यदि हम उन खेतों तक सिंचाई की बेहतर व्यवस्था पहुंचा पाते हैं तो हम ना सिर्फ उत्पादन बढ़ा सकते हैं बल्कि किसानों को लाभ पहुंचा कर, उनकी आत्मनिर्भरता की तरफ एक कदम बढ़ा सकते हैं. . .बहरहाल, किसानों की हो रही उपेक्षा पर समाज और राजनीति दोनों को सोचने की जरूरत है। यदि इस क्षेत्र पर थोड़ा ध्यान दे दिया जाए तो तय मानिए, खेती घाटे का सौदा है, यह जुमला बीते समय की बात होगी।

■ आशीष कुमार 'अंशु'

भारतीय कृषि के लिए चुनौतियों की बात करते हुए नाबार्ड (नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर) के प्रकाश बक्शी कहते हैं– बड़े खेतों का छोटे टुकड़ों में बंटना और देश में छोटे जोत के किसानों की हो रही वृद्धि कृषि क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है। छोटे जोत के किसान सिर्फ किसान होकर अपनी जिन्दगी का निर्वहन नही कर सकते। उन्हें खेती के साथ कुछ और काम करना पड़ता है।'

हमारी खेती की जमीन पिछले 40 सालों से 14 करोड़ हेक्टेयर है। जबकि किसानों की संख्या 14 करोड़ के आसपास है। प्रत्येक पांच साल में एक करोड़ किसानों को खेतों के साथ जोड़ते हैं। छोटी जोत होने की वजह से वह अपने खेत की देखभाल में ठीक प्रकार से खर्च नहीं कर पाता। साथ ही खेत से होने वाली आमदनी कई बार परिवार चलाने तक के लिए पर्याप्त नहीं होती। साथ ही खेत में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। साथ खेत छोटा होने के बावजूद किसान को पूरा समय देना पड़ता है। यदि खेत के क्षेत्रफल और किसानों के बीच बढ़ते इस असमानता को गंभीरता से नहीं लिया गया तो आने वाले समय में कृषि को आत्मनिर्भर व्यावसाय बनाए कठीन होगा। इससे निपटनें के लिए खेती की जमीन के लीज पर दिए जाने के नियम और शर्तों को असान बनाने की जरूरत है। जिससे जमीन लेने वाले को लाभ मिले और जो जमीन का मालिक है, उसका अधिकार भी सुरक्षित रहे। लीज के नियम की कठीनाई की वजह से छोटी जमीन होने की वजह से जो किसान खेती नहीं करते। अपना जीवन यापन मजदूरी या छोटी–मोटी नौकरी से करते हैं, वे भी अपनी जमीन किसी और को खेती के लिए नहीं देते। इसके पिछे उनका यह डर भी काम करता होगा कि जिसे जमीन दी, वह कल उस जमीन पर अपना मालिकाना हक ना जताने लगे। हरियाणा और पंजाब ने काफी हद तक अपने यहां कानूनों सुधार किया है। किसानों को इसका लाभ भी मिला लेकिन तमिल नाडू जैसें राज्य में स्थिति में भिन्न है। जमीन देने का अर्थ आम तौर पर यहां जमीन खो देने से ही लगाया जाता है।

किसानों के लिए भंडार गृह एक बड़ी समस्या है। जिस पर आम तौर सरकारों की तरफ से भी ध्यान नहीं दिया जाता। सरकार ने अपने भंडार गृह जगह–जगह बना रखे हैं। लेकिन सरकार यदि समाज के परंपरागत भंडार गृहों को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करती तो अनाज की बर्बादी जो हर साल पूरा देश देखता है, उसमें काफी हद तक कमी आती। गरीब किसान अच्छी फसल के

बावजूद भंडारण ना कर पाने की मजबूरी में आढ़तियों और बीचौलियों के हाथों बेहद कम दाम में अपनी फसल बेचने को तैयार हो जाता है। यदि उन किसानों के लिए भंडारण की व्यवस्था नहीं हो सकती तो कम से कम सही दाम में उनकी फसल को खरीदने और बेचने की इंतजाम तो सरकार को करना ही चाहिए। इस तरह छोटे किसान गांव स्तर पर खरीददार से अपना अनाज बेचने के लिए मोल–भाव कर पाएंगे। उनमें आत्मविश्वास भी आएगा। सरकार को पीएसीज (प्राइमरी एग्रीकल्चर कॉपरेटिव सोसायटी) पर काम करना चाहिए और उसे नजदीकी भंडार गृह से जोड़ना चाहिए। इसमें मार्केटिंग के लिए एक टीम का गठन किया जा सकता है। जिनकी मदद से किसान अपनी फसल का सही मूल्य ले पाएंगे। सरकार द्वारा 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान भंडार गृह के लिए है। प्राइमरी एग्रीकल्चर कॉपरेटिव सोसायटी की भूमिका पर सरकार यदि ध्यान दे तो वह किसानों के सशक्तिकरण के लिए एक मजबूत आधार हो सकता है। इस तरह की सहकारी समिति अपने सदस्यों के लिए ऋण की व्यवस्थ कर सकता है, अधिक मात्रा में एक साथ पूरे गांव के लिए खाद, बीज जैसी सामग्री खरीदने से दूकानदार भी अच्छी सामग्री देगा और पैसे भी फूटकर खरीद के मुकाबले कम लेगा। देश में काम कर रही लगभग 500 पीएससीज में इस तरह की थोक खरीददारी हो रही है, इन 500 पीएससीज में लगभग 150 तमिलनाडू में हैं। किसानों के लिए सिचाई एक महत्वपूर्ण जरूरत होती है, खेती के दौरान। देश की 55 फीसदी खेती योग्य भूमि वर्षा पर निर्भर करती है। यदि हम उन खेतों तक सिंचाई की बेहतर व्यवस्था पहुंचा पाते हैं तो हम ना सिर्फ उत्पादन बढ़ा सकते हैं बल्कि किसानों को लाभ पहुंचा कर, उनकी आत्मनिर्भरता की तरफ एक कदम बढ़ा सकते हैं।

इस बात पर कृषि वैज्ञानिकों, सरकार और समाज को मिलकर विचार करना चाहिए कि 14 करोड़ हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि अधिक से अधिक बेहतर तरिके से कैसे इस्तेमाल किया जाए? पंजाब और हरियाणा हमारे देश के पारंपरिक अनाज के कटोरे हैं। अब हम हरित क्रांति को देश पूर्वी राज्यों की तरफ ले जा रहे हैं, जो हमारे यहां के मुख्य धान उत्पादक राज्य भी हैं।

किसानों के लिए भंडार गृह एक बड़ी समस्या है। जिस पर आम तौर सरकारों की तरफ से भी ध्यान नहीं दिया जाता। सरकार ने अपने भंडार गृह जगह–जगह बना रखे हैं। लेकिन सरकार यदि समाज के पंरंपरागत भंडार गृहों को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करती तो अनाज की बर्बादी जो हर साल पूरा दे□ा देखता है, उसमें काफी हद तक कमी आती। गरीब किसान अच्छी फसल के बावजूद भंडारण ना कर पाने की मजबूरी में आढ़तियों और बीचौलियों के हाथों बेहद कम दाम में अपनी फसल बेचने को तैयार हो जाता है।

इस तरह का एक सफल प्रयोग 1500 किसानों के साथ बालासोर (ओडिसा) में किया गया। किसानों को वहां धान की खेती श्री विधि से कराई गई। इस विधि ा में अच्छे बीज का इस्तेमाल करें तो फसल अच्छी होती है और पानी की खपत कम होती है।

किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ भी किसान उठा हरे हैं। पिछले सात सालों में अस्सी हजार करोड़ से छह लाख करोड़ रुपयों का ऋण किसानों ने उठाया है। सब–कुछ कम्प्यूटराइज हो जाने से लेन–देन की प्रक्रिया सरल हुई है। किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर कुछ शिकायतें भी सुनने को मिली। किसानों की शिकयतों को गंभीरता से लेते हुए, क्रेडिट कार्ड में समय के साथ सुधार की जरूरत है।

हॉर्टिकल्चर किसानों के लिए लाभ का सौदा हो सकता है लेकिन ना जाने क्यों इस कारोबार की तरफ अब तक सरकार का ध्यान है और बैंकिंग कंपनियों का। इसके साथ यदि किसान सब्जियों की खेती और व्यावसाय में आएं तो भी यह सौदा फायदे का होगा। लेकिन यहां गौर तलब है कि किसानों के खेत से निकलकर थोक बाजार में पहुंचने तक 15 फीसदी सब्जी का नुक्सान हो चुका होता है। थोक बाजार में 25 फीसदी सब्जी खराब हो जाती है। खुदरा बाजार में यह दर 15 से 20 फीसदी का है। इन वजहों से किसानों को लाभ भी कम मिलता है और ग्राहक को यह महंगी भी मिलती है।

यदि हम खराब होने वाली फल सब्जियों का सही प्रकार से पैकेजिंग करें और उनके ट्रांसपोर्ट पर ध्यान दे तो निश्चित तौर पर इसका लाभ हमारे किसानों को मिलेगा। इसके लिए एपीएमसी एक्ट में भी बदलाव की जरूरत है।

बहरहाल, किसानों की हो रही उपेक्षा पर समाज और राजनीति दोनों को सोचने की जरूरत है। यदि इस क्षेत्र पर थोड़ा ध्यान दे दिया जाए तो तय मानिए, खेती घाटे का सौदा है, यह जुमला बीते समय की बात होगी। ❑

समीक्षा

किसानों की राजनीतिक ताकत

आगामी कुछ वर्षों में देश को महाशक्ति बनाने वालों की आवाज का तब तक कोई मूल्य नहीं, जब तक कि देश की दो तिहाई आबादी गरीबी और भूख में रहने को विवश है। हालिया अध्ययनों के मुताबिक भारत में 60 फीसद किसान भूख की कगार पर हैं। किसी किसान का भूखे पेट सोना कृषि क्षेत्र में व्याप्त भयावह संकट को रेखांकित करता है। हालांकि अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। यही समय है जब पूरे देश के किसान संगठनों को संगठित होकर चुनाव से पूर्व एक एकीकृत योजना पेश करनी चाहिए।

■ **देविन्दर शर्मा**

वर्ष 2014 का लोकसभा चुनाव अब नजदीक है और जब चुनाव नजदीक आता हैं तो सरकार की नींद अचानक टूटती है। उसे आम लोगों के प्रति अपने कर्तव्य की याद आती है। यह वर्ष भी अपवाद नहीं है। फिर बात चाहे सेवानिवृत्त रक्षाकर्मियों के वन रैंक–वन पेंशन की हो, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत गरीबों को हर माह मिलने वाले अनाज की हो अथवा केंद्रीय सरकारी कर्मियों के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि समेत सातवें वेतन आयोग की घोषणा की हो या फिर जाट आरक्षण के ऐलान की। कुल मिलाकर यह सूची बहुत लंबी है।

यह चुनावी उपहार का समय है। आप जितने ज्यादा संगठित हैं और जितना अधिक आपका जनाधार है, आपके लिए संभावनाएं भी उतनी ही अधिक हैं, लेकिन आश्चर्य यह कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा होने के बावजूद किसान अभी भी उपेक्षित हैं। कुल आबादी का 54 फीसद हिस्सा किसानों का है। किसान और भूमिहीन कृषि मजदूरों की कुल आबादी तकरीबन 60 करोड़ है। बावजूद इसके इस विशाल आबादी को जबानी सहानुभूति के अलावा और कुछ नहीं मिला है। न केवल वर्तमान संप्रग सरकार, बल्कि दूसरी बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने भी किसानों की बदहाली पर ध्यान देना शायद ही जरूरी समझा हो।

सच्चाई यही है कि किसी भी दल के चुनावी रडार पर किसानों की चिंता नदारद है। मेरठ में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने गन्ने के दाम बढ़ाने की बात कही। उन्होंने 5000 करोड़ रुपये का कोष बनाने की बात कही, ताकि किसानों को अपनी फसलों के लिए पर्याप्त बाजार मूल्य हासिल हो सके। गुजरात कृषि मॉडल की चर्चा करते हुए उन्होंने नकदी फसलों की भी बात की तो

दूसरी ओर राहुल गांधी के भाषणों में किसानों की चर्चा गायब दिखती है। वह युवाओं और महिलाओं के बारे में बात करते हैं, लेकिन कृषि और किसानों पर शायद ही कुछ बोलते हैं। पंजाब में प्रकाश सिंह बादल ने कृषि सब्सिडी में कमी के सुझाव को खारिज कर दिया है। दरअसल वह जानते हैं कि वहां कुल 1.92 करोड़ मतदाताओं में से तकरीबन आधे किसान हैं। हालांकि उनके द्वारा स्वीकृत 7,200 नलकूप पिछले दशक भर से लंबित हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवारों को बकाया क्षतिपूर्ति देने की बात कही है। हालांकि इसके लिए किसानों को तकरीबन सप्ताह भर धरना–प्रदर्शन करना पड़ा।

बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि के कारण फसलों को हुए नुकसान के एवज में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी केंद्र से किसानों को 5000 करोड़ रुपये मदद देने की मांग को लेकर धरना दिया। किसानों को खुश रखने के लिए अन्य राज्यों की सरकारें भी समय समय पर सहायता राशि की घोषणाएं करती हैं, लेकिन किसानों की कृषिगत आय में असमानता कम करने के लिए शायद ही कुछ किया गया है।

पूरे देश में एक बड़ा वोट बैंक होने के बावजूद किसानों की स्थिति में खास अंतर नहीं आ सका है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि एक समुदाय के रूप में वे बंटे हुए हैं और विभिन्न आधारों पर मतदान करते

भारत में बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण शहरीकरण के नाम पर किया गया है। यहां तक कि विदेशी कंपनियों को भी यह सुविधा दी जा रही है। ऐसे तकरीबन 31 उपक्रम अथवा समझौते प्रक्रिया के चरण में हैं। इसके लिए बढ़ती आबादी का हवाला दिया जाता है। अब चीन भी कृषि भूमि के अधिग्रहण की अपनी गलती को सुधार रहा है। कृषि को आर्थिक रूप से लाभप्रद और टिकाऊ बनाने की आवश्यकता है। खेती अब भी सबसे बड़ा रोजगार क्षेत्र है। कृषि में रोजगार खत्म करना और शहरों में छोटी नौकरियां पैदा करना आर्थिक विकास नहीं है।

हैं, न कि एकीकृत किसान शक्ति के रूप में। इन वजहों से कोई भी राजनीतिक दल उन्हें गंभीरता से नहीं लेता। हालांकि ज्यादातर कमियां किसान संघों और संगठनों के नेतृत्वकर्ताओं की है। इनमें से ज्यादातर खुद लोकसभा टिकट के लिए लालायित हैं और नेताओं के समक्ष नतमस्तक हैं। यदि आज किसान बड़ी राजनीति शक्ति नहीं बन सके हैं तो इसके लिए यही लोग जिम्मेदार हैं।

एक ऐसे समय में जबकि किसान परिवारों की औसत मासिक आमदनी 2,115 रुपये है और प्रतिदिन 2,500 किसान खेती–बाड़ी के काम को छोड़ रहे हैं तो राजनीतिक दलों को चाहिए कि वे कृषि को पुनर्जीवित करने के लिए तत्काल ध्यान दें।

आगामी कुछ वर्षों में देश को महाशक्ति बनाने वालों की आवाज का तब तक कोई मूल्य नहीं, जब तक कि देश की दो तिहाई आबादी गरीबी और भूख में रहने को विवश है। हालिया अध्ययनों के मुताबिक भारत में 60 फीसद किसान भूख की कगार पर हैं। किसी किसान का भूखे पेट सोना कृषि क्षेत्र में व्याप्त भयावह संकट को रेखांकित करता है। हालांकि अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। यही समय है जब पूरे देश के किसान संगठनों को संगठित होकर चुनाव से पूर्व एक एकीकृत योजना पेश करनी चाहिए। उन्हें साफ संदेश देना चाहिए कि किसान उन्हीं राजनीतिक दलों को वोट देंगे जो सत्ता में आने पर उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन देंगे। इसके लिए 20 सूत्रीय मांग बनाई जा सकती है, जिन पर तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

इनमें एक मांग किसानों के लिए राष्ट्रीय किसान आय आयोग के गठन की है। एक ऐसे समय जब डब्ल्यूटीओ किसानों को दिए जाने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य का विरोध कर रहा है और दूसरे इससे महज 30 फीसद किसानों को ही फायदा पहुंच रहा है तो सरकार को चाहिए कि वह किसानों को प्रति माह एक निश्चित घरेलू आय पैकेज प्रदान करे। यदि उत्तर प्रदेश में मायावती सफाई कर्मचारियों को प्रति माह 18,500 रुपये वेतन दे सकती हैं तो किसानों को निश्चित आय, महंगाई भत्ता, स्वास्थ्य और चिकित्सा भत्ता समेत पेंशन लाभ क्यों नहीं दिया जा सकता? यदि पंजाब में मंडियों और संपर्क मार्गों के विस्तृत नेटवर्क के माध्यम से

किसानों को उनके कृषि उत्पादों के लिए समुचित कीमत मिल सकती है तो पूरे देश में क्यों नहीं? उदाहरण के लिए बिहार में मंडियों के अभाव में व्यापारी किसानों वर्षो से ठगते आ रहे हैं।

रासायनिक कीटनाशकों और खाद के अत्यधिक इस्तेमाल से न केवल कृषि भूमि की उर्वरता नष्ट हो रही है, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों का आधार खत्म हो रहा है और भूमिगत जल प्रदूषित हुआ है। इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ी हैं। इस कारण टिकाऊ खेती के लिए देशव्यापी मिशन शुरू करने की आवश्यकता है। आंध्र प्रदेश में 35 लाख एकड़ से अधिक जमीन पर आज गैरकीटनाशक प्रबंधन उपायों को अपनाया गया है। वहां किसान 20 लाख हेक्टेयर जमीन पर रासायनिक खादों का प्रयोग त्याग चुके हैं। बावजूद इसके वहां उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा कृषि भूमि का गैर कृषि कार्यो के लिए इस्तेमाल बंद होना चाहिए। भारत में बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण शहरीकरण के नाम पर किया गया है। यहां तक कि विदेशी कंपनियों को भी यह सुविधा दी जा रही है। ऐसे तकरीबन 31 उपक्रम अथवा समझौते प्रक्रिया के चरण में हैं। इसके लिए बढ़ती आबादी का हवाला दिया जाता है।

अब चीन भी कृषि भूमि के अधिग्रहण की अपनी गलती को सुधार रहा है। कृषि को आर्थिक रूप से लाभप्रद और टिकाऊ बनाने की आवश्यकता है। खेती अब भी सबसे बड़ा रोजगार क्षेत्र है। कृषि में रोजगार खत्म करना और शहरों में छोटी नौकरियां पैदा करना आर्थिक विकास नहीं है। ❑

कैसा सांसद चुनेंगे आप?

महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गरीबी–अमीरी के अन्तर को कैसे रोकना है ये सभी काम आप के चुने हुए सांसद के हाथ में होगा। फिलहाल अभी आप को उनका चुनाव करना है। इसके लिए चुनाव के दिन मतदान स्थल पर जाकर आपको इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन का बटन उनके चुनाव चिन्ह पर दबाकर करना है। इसलिए इस काम को आपको बहुत सोच समझकर करना होगा।

■ निरंकार सिंह

सोलहवीं लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। आप का सांसद कैसा हो, अब यह देश के मतदाताओं को तय करना है। देश से 543 संसद सदस्य चुने जाने हैं। सभी राजनीतिक दलों के और कुछ निर्दल उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। जिन्हें आप चुनेंगे, वही आपकी तकदीर लिखेंगे। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गरीबी–अमीरी के अन्तर को कैसे रोकना है ये सभी काम आप के चुने हुए सांसद के हाथ में होगा। फिलहाल अभी आप को उनका चुनाव करना है। इसके लिए चुनाव के दिन मतदान स्थल पर जाकर आप को इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन का बटन उनके चुनाव चिन्ह पर दबाकर करना है। इसलिए इस काम को आपको बहुत सोच समझकर करना होगा। हर पांच साल में एक बार यह मौका आपको मिलता है कि जिसमें आप अपनी पसंद का सांसद लोकसभा में भेज सकते हैं। जो केन्द्र में नई सरकार के गठन में योगदान देता है। इस बार केन्द्र में सरकार बनाने के लिए मुख्य मुकाबला भाजपा के प्रधानमंत्री पद के घोषित उम्मीदवार नरेन्द्र मोदी और कांग्रेस के राहुल गांधी के बीच हो रहा है। कई क्षेत्रीय दल भी हैं जो इस चुनाव में सत्ता की चाभी अपने हाथ में रखने के लिए लालायित हैं। इन क्षेत्रीय दलों के कई नेता ऐसे हैं जिनकी आय से अधिक दौलत होने के मामलों की सीबीआई जांच भी कर रही है। जाहिर है कि इनका मूल मकसद यह है कि उन्हें लोकसभा में इतनी सीट मिल जाए ताकि किसी एक दल को बहुमत नहीं मिल पाने की स्थिति में वह सौदेबाजी करके नई सरकार से अपने मामले को रफा–दफा कर सके और फिर अपना राजनीतिक धंधा करने में जुट जाएं। उनके लिए सरकार में भागीदारी का उद्देश्य सिर्फ निजी स्वार्थो तक सीमित हो गया है। लोककल्याण और विकास की भावना कई क्षेत्रीय दलों में दिखाई नहीं देती है। जातिवाद और सेकुलरवाद को आधार बनाकर वे सिर्फ अपना और कुछ अपने लोगों का ही भला करते रहे हैं। आज देश को ऐसे सांसदों या दलों की जरूरत है कि वे देश और उसकी जनता की सेवा और भलाई के लिए त्याग, तपस्या और बलिदान का जज्बा रखते हों। अब यह सब आपको तय करना है।

लोकसभा और विधान सभाओं में अपराधियों की बढ़ती संख्या से पता चलता है कि हमारी पूरी संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली खतरे में है। पैसा बांटकर कई राजनीतिक नेता जनता का भी वोट खरीदते रहे हैं। दरअसल लोकतंत्र में जैसे हम होंगे वैसे ही हमारे नेता होंगे। जब लोग जाति, धर्म ओर लालच में आकर वोट देंगे तो ईमानदार और चरित्रवान प्रतिनिधि कहां से आयेंगे। संसदीय लोकतंत्र में भारी गठरी, ठग विद्या, और संचार के आधुनिक साधनों की सहायता से बड़े–बड़े राजनीतिक आज जिस कांइयापन से आम चुनाव में अपने पक्ष में प्रचार करते हैं उसे देखते हुए यही कहा जा सकता है कि ये निर्वाचक मतदाताओं का नहीं, बल्कि उन शक्तियों और हितों का प्रतिनिधित्व करते

हैं जो दलों को शिखंडी बनाकर अपना काम निकालने के लिए तैयार रहते हैं। संसदीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यदि हमारे राजनीतिक दल चुनाव में किये गये वादे और अपने घोषणा पत्रों पर अमल नहीं करते है तो निर्वाचक मतदाता क्या कर सकते हैं। मत प्राप्त करने के लिए मतदाताओं को फंसाने के लिए तरह–तरह के अर्ध सत्य और कभी–कभी पूरी तरह असत्य बातों का आश्रय लिया जाता है। लोगों को उत्तेजित किया जाता है और कई बार उनकी कुत्सित भावनाओं को जगाया जाता है तथा झूठे किन्तु मीठे वादे करके फुसलाया जाता है। सार्वजनिक हित से सम्बद्ध किसी प्रश्न का सही रूप जनता के सामने प्रस्तुत नहीं किया जताा है। इसके विपरीत तिकड़मी ढंग से अपने पक्ष के अनुकूल बातें तोड़ मरोड़ कर उपस्थित की जाती हैं। इस तिकड़मवाद की वेदी पर राष्ट्र के वास्तविक हितों की बलि चढ़ा दी जाती है। आखिर क्या कारण है कि आजादी के 67 वर्षो के बाद भी सबके लिए पीने और सभी खेतों को सींचने के लिए पानी का इंतजाम नहीं हो सका है। पानी, बिजली, सड़क, अस्पताल, रोजगार, शिक्षा, सिंचाई की समस्याओं का हमारे राजनेताओं के पास क्या जवाब है? जनता जब विकास का हिसाब मांगती है तो हमारे राजनेता बगले झांकने लगते हैं या एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में उलझ जाते हैं।

देश में लोकतंत्र की आज जो दशा है उसके लिए जनता जिम्मेदार है। अपराधी जिसके हाथ खून से रंगे हुए हैं सभी दलों में प्रवेश कर चुके हैं। वे विधायक, सांसद और मंत्री तक हो गये हैं। अब यदि लोकतंत्र असफल सिद्ध होता है और हिंसा से भी कोई नतीजा नहीं निकलता है तो फिर रास्ता क्या है? यह रास्ता गांधी जी ने बताया है। गांधी जी हिंसा की व्यर्थता तथा लोकतांत्रिक राज की स्वाभावगत सीमाओं से परिचित थे इसलिए उनकी योजना राज्य शक्ति के साथ लोकशक्ति के निर्माण की थी। वैसे भी किसी देश में लोकतंत्र की सफलता जनता की जागरूकता पर ही निर्भर करती है। लेकिन हमारे देश में लोक शिक्षण के लिए किसी नेता ने कभी कोई गंभीर प्रयास नहीं किया। यह देश का दुर्भाग्य ही रहा कि आजादी के कुछ ही समय बाद गांधी जी की हत्या हो गयी और दूसरी आजादी के बाद भी जयप्रकाश नारायण अधिक दिनों के बाद जीवित नहीं रह सके इसलिए लोक शिक्षण का कार्य नहीं हो सका। जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि जनता जब तक खुद खड़ी नहीं होगी उसकी कोई मदद नहीं कर सकता है। यदि हमारे नेता भ्रष्ट, बेईमान और अपराधी हैं तो इसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं। लोकतंत्र में जनता ही अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। यदि हम जाति, बिरादरी या धर्म के नाम पर गुंडो, बदमाशों का चुनाव करेंगे तो फिर जैसा लोकतंत्र बनेगा वह आपके सामने है।

देश की विशाल मानव–शक्ति अभी खर्राटे ले रही है और देश की उपयोगी पूँजी बनने के बदले आज बोझ बन गयी है। किन्तु इसमें राजकीय पक्षों का, सरकार की नीति का भी बहुत दोष है। इस कारण भी जनता निष्क्रिय बनी रहती है। बहुत से लोग तो सरकार की आलोचना करते हैं लेकिन मतदान के जरिए जब सरकार बदलने की बारी आती है तो मतदान करने भी नहीं जाते हैं। इसलिए अधिकारों और कर्तव्य को जानिये। लोकतंत्र में हम जैसे होंगे वैसी ही हमारी सरकार भी होगी। कुल मिलाकर हमारे लोकतंत्र की समस्या मूलतः नैतिक है। संविधान, शासन प्रणाली, दल, निर्वाचन ये सब लोकतंत्र के अनिवार्य अंग हैं। किन्तु जब तक लोगों में नैतिकता की भावना नहीं रहेगी, लोगों का आचार विचार ठीक नहीं रहेगा तब तक अच्छे से अच्छे संविधान और राजनीतिक प्रणाली के बावजूद लोकतंत्र ठीक ढंग से काम नहीं कर सकता है। लोकतंत्र के लिए ये नैतिक गुण और मानसिक प्रवृत्तियां आवश्यक हैं। यदि देश को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से सम्पन्न और आत्मनिर्भर बनाना है तो हमें अपने लोकतंत्र को गुण तंत्र में बदलना होगा। आप जिस किसी उम्मीदवार का चुनाव करेंगे वह नयी सरकार के गठन में महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके लिए जरूरी है कि आप सभी लोग जो मतदाता बन चुके हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। आप जिसे भी चुने सोच समझ कर चुनें। आपके मतदान से ही लोकतंत्र में सरकारें बनती बिगड़ती हैं। इसलिए बिना लोभ, लालच या भय के अपने मताधिकार का प्रयोग करें। जाति, बिरादरी, सम्प्रदाय धर्म से ऊपर उठकर योग्य और ईमानदार उम्मीदवार का चुनाव करके अपने लोकतंत्र को मजबूत बनाइए। ❑

जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि जनता जब तक खुद खड़ी नहीं होगी उसकी कोई मदद नहीं कर सकता है। यदि हमारे नेता भ्रष्ट, बेईमान और अपराधी हैं तो इसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं। लोकतंत्र में जनता ही अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। यदि हम जाति, बिरादरी या धर्म के नाम पर गुंडो, बदमाशों का चुनाव करेंगे तो फिर जैसा लोकतंत्र बनेगा वह आपके सामने है।

ईमान की कसौटी पर होगी अगली सरकार

कुछ सालों पहले तक एक आम राय यह बन गई थी कि भ्रष्टाचार अब राजनीति में महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं रहा। पर इन चुनावों में ऐसा नहीं है। भ्रष्ट नेताओं की मुश्किलें बढ़ रही हैं। भ्रष्टाचार का ताल्लुक सिर्फ नेताओं के नोट खाने से नहीं है, बल्कि पूरे आर्थिक विकास से है . . जो भी सरकार आने वाले दिनों में केंद्र में बनेगी, वह ईमान को अर्थव्यवस्था का आधार बनाएगी, तो ही उसकी राजनीति को मजबूती मिलेगी। तेजी से विकसित अर्थव्यवस्था में उसकी कुछेक गलतियां भी माफ हो जाएंगी। निकम्मी और भ्रष्ट शासन की कुछ उपलब्धियों को भी पब्लिक मानने को तैयार नहीं होती, यह बात अभी की सरकार की हालत देखकर समझी जा सकती है।

■ आलोक पुराणिक

लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आर्थिक मसले बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। बल्कि इन चुनावों में आर्थिक मसले निर्णायक साबित होने जा रहे हैं। सिर्फ सेकुलर–सेकुलर कहकर चुनाव जीतने वालों को इस बार पसीने आ रहे हैं। सैकुलर के खोल में करप्शन छिपाना अब आसान नहीं हो रहा है। पब्लिक अब व्यंग्यात्मक लहजे में पूछने लगी है कि आप सैकुलर हैं, ठीक है, पर यह बताइए कि करप्शन क्या सैकुलर होने के लिए अनिवार्य शर्त है! इंडिया की राजनीति थोड़ी सी बदली दिखायी दे रही है। महंगाई और विकास के मसले पर सवाल पूछे जा रहे हैं और जवाब मांगे जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की राजनीति से कोई लाख असहमति रखे, पर उस राजनीति ने उन सवालों को बीच बहस में ला दिया है, जिनसे आंख चुराकर तमाम नेता निकल लेते थे। विकास विकास के हल्ले में कोई नेता अपने दोस्तों–दामादों को अमीर बना लेगा और लोग कुछ नहीं पूछेंगे, ऐसा अब की बार नहीं हो रहा है। हरेक से सवाल पूछे जा रहे हैं और हरेक को जवाब देने पड़ रहे हैं।

पुराने आचरण को छोड़ना एकदम संभव नहीं हो पा रहा है, तो भी जवाब तो देने ही पड़ रहे हैं। कुछ सालों पहले तक एक आम राय यह बन गई थी कि भ्रष्टाचार अब राजनीति में महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं रहा। पर इन चुनावों में ऐसा नहीं है। भ्रष्ट नेताओं की मुश्किलें बढ़ रही हैं। भ्रष्टाचार का ताल्लुक सिर्फ नेताओं के नोट खाने से नहीं है, बल्कि पूरे आर्थिक विकास से है। नेता पूरी दुनिया में ही भ्रष्टाचार की गंगोत्री हैं।

चीन जैसी अर्थव्यवस्था में एक तिहाई अरबपति चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर हैं। चीन के वरिष्ठ नेताओं को समझ में आ रहा है कि भ्रष्टाचार खत्म नहीं किया गया या कम नहीं किया गया, तो अर्थव्यवस्था के सम्मुख समस्या खड़ी होने में देर नहीं लगेगी। भ्रष्टाचार सिर्फ कुछ लोगों को अमीर बनाने का मसला नहीं है। भ्रष्टाचार अर्थव्यवस्था में कुशलता को हतोत्साहित करके अकुशलता को प्रोत्साहित करने का भी मसला है। जुगाड़ से, रिश्वत देकर टेलीकॉम लाइसेंस हासिल करनेवाले क्या करेंगे या तो वह खराब टेलीकॉम सेवाएं देंगे या फिर अपने लाइसेंस को आगे बेच देंगे। तमाम तरह की फीस आखिर में कौन चुकाता है? वह उपभोक्ता द्वारा चुकायी जाती है।

लाइसेंस, कारोबार करने के मौके अगर योग्य व्यक्तियों के हाथों में रहें, तो लागत सस्ती होगी। उपभोक्ताओं का भला होगा। भ्रष्ट अर्थव्यवस्था कुशल अर्थव्यवस्था के खिलाफ काम करती है। तेज गति का विकास तभी संभव है, जब भ्रष्टाचार विहीन अर्थव्यवस्था काम करे। लोकतंत्र पब्लिक को मौके देता है कि वह भ्रष्ट नेताओं को उखाड़ फेंके और दूसरों को मौका दे। चीन में इस तरह के मौके नहीं हैं पर भारत में हैं। मोदी के भाषणों को लगातार देखें, तो वह विकास और

सुशासन की ही बात कर रहे हैं। विकास होता है तो पब्लिक को आर्थिक अनुदान रेखा से ऊपर उठाया जा सकता है।

तमाम तरह की योजनाओं की आड़ में पब्लिक को अनुत्पादक आर्थिक सहायता देकर, अनुदान देकर राजनीतिक दल वोट हासिल करना चाहते हैं। इस तरह की योजनाओं से मोटे तौर ऐसे लोग पैदा होते हैं जो उत्पादक काम न करके, अपने हिस्से

के अनुदान अपना अधिकार मानने लगते हैं। तमाम योजनाओं में हर स्तर पर कट–कमीशन तय होते हैं। न्यस्त स्वार्थों की श्रृंखला पैदा हो जाती है। संसाधनों का इस्तेमाल रिश्वत देने में होने लगता है। कुशलता खत्म होती जाती है। विकास तेज गति से हो, तो अनदान की जरूरत नहीं रहती। तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था हर नागरिक से यह उम्मीद करती है कि वह अपनी क्षमताओं से इस अर्थव्यवस्था में अपना हिस्सा ले ले। अर्थव्यवस्था के अत्यधिक विपन्न तबके के लिए सामाजिक सुरक्षा का इंतजाम सरकार करे, ऐसी उम्मीद सरकार से की जाती है। पर हो उलटा रहा है।

भ्रष्ट नेताओं, अफसरों की सामाजिक सुरक्षा का इंतजाम तो सरकारी संसाधनों से हो रहा है और समाज का विपन्न वर्ग अपने हाल पर रोते रहने के लिए छोड़ दिया गया है। अर्थव्यवस्था का यह मॉडल समाजवादी मॉडल के नाम पर धुआंधार चल रहा है। करीब दस साल पहले जब अर्थव्यवस्था के दस प्रतिशत हर साल विकास की बात हो रही थी, तब नाउम्मीदी, बेरोजगारी जैसी बातें नहीं हो रही थीं। अब पांच प्रतिशत विकास की बात भी बहुत मुश्किल से हो पा रही है। अब अर्थव्यवस्था में कुछ उद्योगपतियों को छोड़कर सब परेशान हैं।

जिनकी सैटिंग सरकार के साथ है, वह मजे में हैं, बाकियों की आफत है। तरह–तरह के मंत्रालय, तरह–तरह के लाइसेंस, तरह–तरह के चढ़ावे कारोबार कैसे हो। कारोबार न हो, तो रोजगार कैसे बढ़े? रोजगार ना हो, तो बंदा जीये कैसे? इतनी सीधी सी बात समझ में ना आती हो, नेताओं को, ऐसा नहीं है। पर समझ से बड़े स्वार्थ होते हैं। स्वार्थ हैं कि उसे लाइसेंस मिले, इसे परमीशन मिले। सर्वश्रेष्ठ को नहीं, अपने बंदे को मिले काम। कांग्रेस सरकार के पतन के कारणों में यह कारण बहुत बड़ा है कि भ्रष्ट और निकम्मे लोगों को इस सरकार ने बहुत मौके दिये। तेज गति से विकसित होती अर्थव्यवस्था में कुछ बुराईयां छिप जाती हैं पर जब सारा काम ही निकम्मेपन और भ्रष्टाचार का हो, तो बुराइयां कहां से छिपेंगी? ईमान से अर्थव्यवस्था चलाना, इस चुनाव के बाद आयी सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए।

कोयला खान समेत तमाम खानों के लाइसेंस में भ्रष्टाचार इस सरकार की कारगुजारियों में एक है। कोयले में घपला है, सो कोयला आयात होगा। कोयला आयात होगा, तो भारत में विदेशी मुद्रा

चीन जैसी अर्थव्यवस्था में एक तिहाई अरबपति चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर हैं। चीन के वरिष्ठ नेताओं को समझ में आ रहा है कि भ्रष्टाचार खत्म नहीं किया गया या कम नहीं किया गया, तो अर्थव्यवस्था के सम्मुख समस्या खड़ी होने में देर नहीं लगेगी। भ्रष्टाचार सिर्फ कुछ लोगों को अमीर बनाने का मसला नहीं है। भ्रष्टाचार अर्थव्यवस्था में कुशलता को हतोत्साहित करके अकुशलता को प्रोत्साहित करने का भी मसला है। जुगाड़ से, रिश्वत देकर टेलीकॉम लाइसेंस हासिल करनेवाले क्या करेंगे या तो वह खराब टेलीकॉम सेवाएं देंगे या फिर अपने लाइसेंस को आगे बेच देंगे। तमाम तरह की फीस आखिर में कौन चुकाता है? वह उपभोक्ता द्वारा चुकायी जाती है।

कोष पर बोझ पड़ेगा। विदेशी मुद्रा कोष पर बोझ पड़ेगा, तो रुपये की डॉलर के मुकाबले पिटाई होगी। रुपया डॉलर के मुकाबले पिटेगा तो आयात महंगे होंगे। आयात महंगा होगा, तो फिर विदेश मुद्रा कोष पर बोझ पड़ेगा। आयात महंगे होंगे, तो स्थानीय बाजारों में महंगाई बढ़ेगी। यानी कोयला मंत्री के भ्रष्ट और निकम्मे आचरण का खमियाजा पूरी अर्थव्यवस्था भुगतेगी। रिजर्व बैंक का रघुराम राजन जैसा कुशल गवर्नर भी इस भ्रष्ट और निकम्मे आचरण की काट नहीं तलाश पायेगा। यही हो रहा है, इसलिए भ्रष्टाचार सिर्फ राजनीतिक आचरण का विषय नहीं रह गया है। यह पूरे तौर पर आर्थिक गतिविधि के केंद्र में आ गया है। पब्लिक जितनी जल्दी इसे समझ लेगी, देश की हालत उतनी तेजी से बेहतर होगी।

इन चुनावों से पहले दिख रहा है कि पब्लिक इसे समझ रही है। वरना कोई और वक्त होता, तो भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में अपने पुराने सहयोगी ओमप्रकाश चौटाला की पार्टी से चुनावी तालमेल बहुत पहले कर लेती। यह तालमेल बहुत आसान हुआ करता था, जब राजनीति में भ्रष्टाचार को कोई मुद्दा नहीं माना जाता था। पर अब भाजपा चौटाला के साथ नहीं जा रही है। चौटाला परिवार हरियाणा में भ्रष्टाचार के कई आरोपों में घिरा हुआ है। भ्रष्टों के साथ दिखने से परहेज होने लगा है, यह भी कम बड़ी बात नहीं है लोकतंत्र के लिए। जो भी सरकार दो महीने बाद केंद्र में बनेगी, वह ईमान को अर्थव्यवस्था का आधार बनायेगी, तो ही उसकी राजनीति को मजबूती मिलेगी। तेजी से विकसित अर्थव्यवस्था में उसकी कुछेक गलतियां भी माफ हो जाएंगी। निकम्मे और भ्रष्ट शासन की कुछ उपलब्धियों को भी पब्लिक मानने को तैयार नहीं होती, यह बात मौजूदा सरकार की हालत देखकर समझी जा सकती है। ईमान लोकतंत्र की मुख्यधारा में है, लोकतंत्र के लिए यह शुभ है। ईमान सरकार बनने के बाद भी मुख्यधारा में रहे, इसकी कामना की जा सकती है। ❑

:: सदस्यता संबंधी सूचना ::

मान्यवर,,

स्वदेशी पत्रिका आज देश में चल रहे स्वदेशी आंदोलनों का स्थापित प्रतीक बन चुकी है। पिछले कई वर्षों से स्वदेशी पत्रिका ने असंगत एवं एकतरफा वैश्वीकरण, जनविरोधी आर्थिक उदारीकरण के विरोध एवं वैकल्पिक और रचनात्मक स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में एक सक्रिय प्रहरी के नाते हमेशा आपको जागरूक बनाया है एवं आपसे संवाद स्थापित किया है। विगत कालखंड में इन सभी मुद्दों पर हमें आप जैसे सजग पाठकों का अपेक्षित सहयोग भी मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलेगा ऐसा, विश्वास है।

आपसे आग्रह है कि स्वदेशी पत्रिका की आपकी सदस्यता अवधि यदि समाप्त हो गई हो तो कृपया पिछले समय से आगामी वर्ष तक की राशि धनादेश (मनीआर्डर), चेक एवं मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से शीघ्र भेजने की कृपा करें। पत्रिका के लिफाफे के उपर चिपकाए गए पते की प्रथम पंक्ति में सदस्यता अवधि अंकित है। आप अपनी सदस्यता राशि ''स्वदेशी पत्रिका'' के नाम पत्रिका के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। सदस्यता अद्यतन न हो पाने की स्थिति में वित्तीय कारणों से पत्रिका आगे जारी रखना कठिन होगा।

सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार है :–

स्वदेशी पत्रिका	वार्षिक	आजीवन
हिन्दी	150 रुपए	1500/– रुपए
अंग्रेजी	150 रुपए	1500/– रुपए

हमें आपका सहयोग स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी एवं जनोन्मुखी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। कृपया स्वदेशी पत्रिका स्वयं भी पढ़ें एवं अन्य को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पत्रिका के संबंध में अपना निष्पक्ष विचार हमें अवश्य भेजें।

आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740 IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram) में जमा करवा सकते हैं और उसकी रसीद और अपना पता आप कार्यालय में अवश्य भेजे।

स्वदेशी पत्रिका कार्यालय, 'धर्मक्षेत्र' शिव शक्ति मंदिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–22

बेडु पाको बारमासा

उत्तराखंड को बस इंतजार है तीर्थयात्रियों और पर्यटको का जो आएं और जो काला तगमा लग गया उत्तराखंड के ऊपर कि अरे यहाँ तो बाढ़ आई थी, वहाँ तो पहाड़ टूटे थे, उस सदमे को हटाने की जरुरत है। आज जरुरत है कि पर्यटक आए और यहाँ रुकें, इस समय अलकनंदा घाटी में इतनी सुंदरता बिखरी हुई है कि आंखे बंद ना हो। पांडुकेश्वर गांव में छः महीने के लिए ब्रदीविशाल जी विराजमान हैं। औली पर्यटन स्थल है। जहां जोशीमठ के पास पहाड़ियों पर बर्फ गिर रही है। सरकारें क्यों नहीं तीर्थाटन और पर्यटन के लिए प्रचार करती है?

■ **विमल भाई**

अभी अलकनंदा सहित सभी नदियां–गंगाएं शांत सुन्दर बह रही हैं। जैसे सारा गुस्सा उतार चुकी हों। सबक दे चुकी हों और अब अपने किनारे बसे लोगो की आजीविका और सुरक्षित भविष्य के लिए चिंतित दिखाई देती हों। मानो वो कहना चाह रही हों कि कसूर किसी का था और बुराई आ गई नदियों पर किंतु

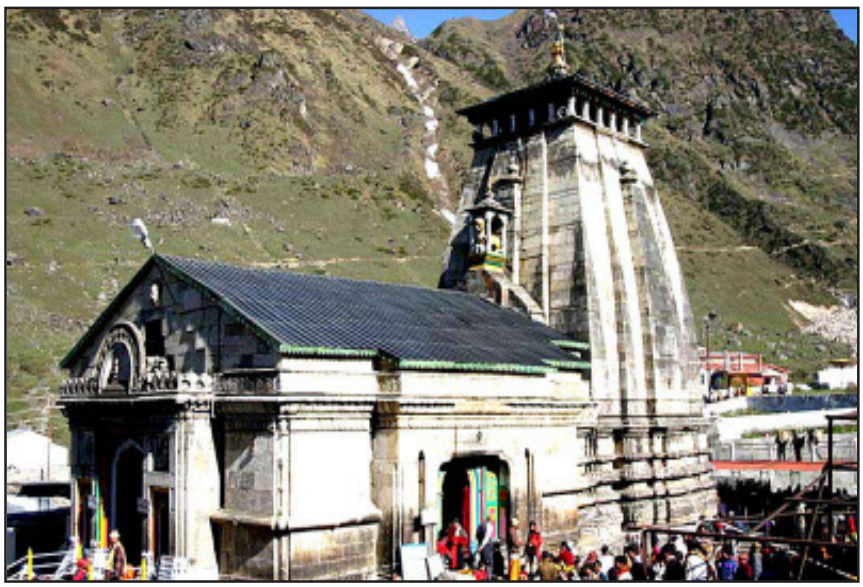

नदियां इसका भी बुरा नहीं मान रही हैं। वो जो कहना चाहती थी उसे उन्होंने अपनी भाषा में जून 2013 में अच्छी तरह से बता दिया है। नदी शांत और सुंदर बह रही है। अभी तेज बारिश में भी नदी बिलकुल शांत अपना हरा रंग लेती बहती हुई अलकनंदा और उसमें मिलती धौलीगंगा, बिरही, गरुड़गंगा, नंदाकिनी, पिंडर, मन्दाकिनी और ना जाने कितनी नदियां मिलकर मानो आमंत्रण ला रही हों नीचे की ओर कि आओ जो होना था वो हो गया और ये फिर होगा अगर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करोगे तो। मगर अभी तो तुम आओ जरूर, मेरे अंचल में आओ, मेरा जल जो प्रकृति का दूध है उसका आनंद लो और बोलो जय उत्तराखंड, मुस्कुराता उत्तराखंड।

ऊपर पहाड़ों में बादल छू रहे हैं, बादल नीचे आके भी छूते हैं। हरियाली फैली हुई है। हाँ, कहीं नीचे इलाकों में बर्फ पड़ी हुई है तो उस हरियाली पर एक सफेद चादर बिछ जाती है मानों प्रकृति ने एक सफेद चादर चांदनी की तरह ओढ़ी हो, जैसे चाँद अपनी रात की चांदनी छोड़ गया हो। नदी के बीच में उभरते हुए, बचे हुए शैवाल, छोटी–छोटी चट्टानें।

हाँ, अलकनंदा के किनारे पर विष्णुप्रयाग बांध और मंदाकिनी पर बन रहे बांधों का मलबा जरूर नजर आता है जो बताता है कि बाँध कंपनियों ने उत्तराखंड की सुन्दर प्रकृति को खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लोग लड़ भी रहे हैं। अलकनंदा नदी पर जेपी कंपनी के विष्णुप्रयाग बाँध के दरवाजे टूटने से नीचे लाम्बगड़, पांडुकेश्वर, गोविंदघाट, विनायक चट्टी आदि में जो तबाही आई। चूंकि उसने 16–17 जून को बाँध के

उत्तराखण्ड सरकार और केन्द्र सरकार ने ज्यादा पैसा तो नहीं दिया है, लोगों ने कर्ज भी लिया है, क्योंकि फिर से बसने की बात है। सब खत्म हो चुका था पर लोग दुबारा यहीं बसना चाहते हैं, उनकी फिर कोशिश है वापिस रास्ते बनाएं, जीवन तो जीना है ना। ये जिंदगी को जीने का जज्बा जो है लोगों में, उसी ने उत्तराखंड को वापिस पटरी पर लाने की कोशिश की है।

दरवाजे बंद रखे। लोग इस तबाही के खिलाफ लड़ रहे हैं और पुनः अपने सौंदर्य के साथ खड़े होने की कोशिश भी है उनकी। दोबारा से नई जगह होटल बनाने की सोच है।

उत्तराखण्ड सरकार और केन्द्र सरकार ने ज्यादा पैसा तो नहीं दिया है, लोगों ने कर्ज भी लिया है, क्योंकि फिर से बसने की बात है। सब खत्म हो चुका था पर लोग दुबारा यहीं बसना चाहते हैं, उनकी फिर कोशिश है वापिस रास्ते बनाएं, जीवन तो जीना है ना। ये जिंदगी को जीने का जज्बा जो है लोगों में उसी ने उत्तराखंड को वापिस पटरी पर लाने की कोशिश की है।

सड़कों पर भरी हुई गाड़ियाँ, सामान से लदे ट्रक और कारों में आते लोग देखकर के जीवन जीने की आस फिर से उमड़ आती है. पिछले साल आई बाढ़ ने जो गढ़वाल और कुमाऊं के क्षेत्रों को तबाही दिखाई थी, आज वो बर्बादी सिमटी हुई नजर आती है। उसको संभालना भी जरूरी है और इसके साथ ये भी समझना जरूरी है कि उत्तराखंड समाप्त कभी नहीं हुआ था। उत्तराखंड फिर से करवट ले कर खड़ा हो रहा है। आओ इस उत्तराखंड को हम फिर से संवारे, प्रकृति के हरे रंग को सफेद चांदनी में लपेटते हुए फिर से देखे। नई सुबह के संग, नए आगाज के संग, आओ फिर उत्तराखंड को पुकारे फिर वही गीत गायें

उत्तराखंड की रीढ़ की हड्डी यानि यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य और लोगों की ताकत। जो बर्बादी को झेलने के बाद भी फिर से खड़े हो रहे हैं। अभी पिछले कुछ महीनों में शादियां खूब जोर–शोर से हुईं। शादियां अभी भी चालू हैं। पहाड़ी शादियां! मस्त, ढोल–नगाड़ों के बीच नाचते हुए लोग देखकर बड़ा सुकून मिलता है। देखकर मन में प्रश्न आ सकता है कि क्या ये वही उत्तराखंड है, जहाँ मात्र 8 महीने पहले भीषण आपदा आई थी? समझ में आ जाना चाहिए कि लोगों ने प्रकृति के साथ जीना सीखा है।

''बेडु पाको बारमासा, ओ नरणी काफल पाको चैत मेरी छैला''।

अलकनंदा के कई किनारे टूटे जरूर हैं। बांधों के टूटने व उनके द्वारा बनाए गए कई कारणों की वजह से भी बहुत सारे लोग प्रभावित जरूर हुए। पर जून 2013 की आपदा की स्थिति याद करने के बाद आज अगर देखो तो मालूम ही नहीं पड़ता कि यहाँ आपदा आई थी। यदि आप उन गाँवों में देखें जिनके बच्चे खत्म हो गए या जिनके घर उजड़ गए। गाँव के गाँव धंस गए। कितनी महिलाएं विधवा हुई, ना जाने कितने बच्चे कहाँ खो गए, किसी को नहीं मालूम? अब आकड़ें फीके पड़ गए हैं। कई सरकारी योजनाएं बनाई गई हैं। ज्यादातर बाहर के लोगों ने, गैर सरकारी संगठन ने, विभिन्न संस्थाओं ने कई प्रकार से मदद की है।

मगर इन सब के बावजूद भी, जो बची हुई है वो है उत्तराखंड की रीढ़ की हड्डी यानि यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य और लोगों की ताकत। जो बर्बादी को झेलने के बाद भी फिर से खड़े हो रहे हैं। अभी पिछले कुछ महीनों में शादियां खूब जोर–शोर से हुईं। शादियां अभी भी चालू हैं। पहाड़ी शादियां! मस्त, ढोल–नगाड़ों के बीच नाचते हुए लोग देखकर बड़ा सुकून मिलता है।

ये सब देखकर मन में प्रश्न आ सकता है कि क्या ये वही उत्तराखंड है, जहाँ मात्र 8 महीने पहले भीषण आपदा आई थी? समझ में आ जाना चाहिए कि लोगों ने प्रकृति के साथ जीना सीखा है। अपनी जिंदगी को सिरे पर लाने के लिए, फिर से उजड़े घर बनाने की, चौपट व्यापार को ठीक करने की कोशिशें जारी है। काफी कुछ तो लोग अपने ही बल पर खड़ा कर रहे हैं। सरकार या अन्य बाहरी मदद भी कहां तक सहयोग दे सकती है। तो लोगों को अपने ही बल पर ही आगे बढ़ना होगा।

फिलहाल उत्तराखंड को बस इंतजार है तीर्थयात्रियों और पर्यटको का जो आएं और जो काला तगमा लग गया उत्तराखंड के ऊपर – कि अरे यहाँ तो बाढ़ आई थी, वहाँ तो पहाड़ टूटे थे, उस सदमे को हटाने की जरुरत है। आज जरुरत है कि पर्यटक आए और यहाँ रुकें, इस समय अलकनंदा घाटी में इतनी सुंदरता बिखरी हुई है कि आंखे बंद ना हो। पांडुकेश्वर गांव में छः महीने के लिए ब्रदीविशाल जी विराजमान हैं। औली पर्यटन स्थल है। जहां जोशीमठ के पास पहाड़ियों पर बर्फ गिर रही है। सरकारें क्यों नहीं तीर्थाटन और पर्यटन के लिए प्रचार करती है? ❑

अभी अलकनंदा सहित सब नदियां–गंगाएं शांत सुन्दर बह रही हैं। जैसे सारा गुस्सा उतार चुकी हों। सबक दे चुकी हों और अब अपने किनारे बसे लोगो की आजीविका और सुरक्षित भविष्य के लिए चिंतित दिखाई देती हों। मानो वो कहना चाह रही हों कि कसूर किसी का था और बुराई आ गई नदियों पर किंतु नदियां इसका भी बुरा नहीं मान रही हैं। वो जो कहना चाहती थी उसे उन्होंने अपनी भाषा में जून 2013 में अच्छी तरह से बता दिया है। नदी की इस भाषा को यदि हम नही समझ पाये तो फिर मुश्किल होगी।

पानी बचाना है तो बिजली बचाइए

विकास के नये पैमनों पर अमेरिका के नजीर के रूप में पेश करनेवाले हमारे नेता अफसर, योजनाकार और खुद नागरिकों ने अमेरिका और खुद के अनुभवों से कुछ नहीं सीखा। नेता, अफसर और योजनाकार भले ही कुछ सीखें न सीखें लेकिन हमारे शहरी समाज को अमेरिका से कम से कम एक बात जरूर सीख लेनी चाहिए कि अगर वे पानी बचाना चाहते हैं तो उन्हें बिजली बचत का संकल्प लेना पड़ेगा।

■ अरुण तिवारी

भारत में पानी पर बात करने के लिए दिवस और भी बहुत हैं। अक्षय तृतीया, गंगा दशहरा, कजरी तीज, देवउठानी एकादशी, कार्तिक पूर्णिमा, मकर संक्रांति आदि आदि। आज भारत के नये विज्ञापनों में पानी की बचत के नुख्से बर्तन धोने, गाड़ी धोने और सिंचाई में किफायत बरतने तक ही सीमित दिखाये जाते हैं। यह हम सब जानते हैं लेकिन आपको जानकर अच्छा लगेगा कि इस मामले में अंतरराष्ट्रीय नजरिया बेहद बुनियादी और व्यापक भी है।

वे मानते हैं कि पानी उर्जा है और उर्जा पानी। यदि पानी को बचाना है तो उर्जा बचाओ। यदि उर्जा बचानी है तो पानी की बचत करना सीखो। बिजली के कम खपत वाले फ्रिज, बल्ब, मोटरें उपयोग में लाओ। पेट्रोल की बजाय प्राकृतिक गैस से कार चलाओ। कोयला व तैलीय ईंधन से लेकर गैस संयत्रों तक को ठंडा करने की ऐसी तकनीकि उपयोग करो कि उसमें कम से कम पानी लगे। उन्हें हवा से ठंडा करने की तकनीकि का उपयोग करो। उर्जा बनाने के लिए हवा कचरा तथा सूर्य का उपयोग करो। फोटोवोल्टिक तकनीकि अपनाओ। पानी गर्म करने, खाना बनाने आदि में कम से कम ईंधन का उपयोग करो। उन्नत चूल्हे तथा उस ईंधन का उपयोग करो जो बजाय किसी फैक्ट्री में बनने के हमारे आसपास हमारे द्वारा तैयार व उपलब्ध हों।

पानी और आग का यह रिश्ता सचमुच बेहद दिलचस्प है। इससे असहमत होना मुश्किल है कि बिजली और ईंधन की बढ़ती खपत के इस युग में उर्जा बचाने पर विचार किये बगैर पानी बचाने की दृष्टि में समग्रता का आना असंभव है। सोचिए, यदि गैस, ईंधन व बिजली जैसे स्रोत ही नहीं होंगे तो हमारी गाड़ियां, ट्यूबवेल, रसोईं के स्टोव कैसे चलेगे? उर्जा न हो तो गर्म पानी की लांड्री में कपड़ा धुलवाना सपना ही रह जाएगा। बिना उर्जा के सालभर तक आलू फल व दूसरे उत्पादों की सुरक्षा कैसे संभव होगी? बर्फ व आइसक्रीम कहां संभव होगी? दूसरी तरफ का नजारा यह है कि यदि ताजे पानी की कमी हो गई तो हम पेट्रोल, प्लास्टिक, लोहा, बिजली, गैस जैसे तमाम जरूरी हो चुके उत्पादनों से मरहूम रह जाएंगे।

पानी और आग का यह रिश्ता सचमुच बेहद दिलचस्प है। इससे असहमत होना मुश्किल है कि बिजली और ईंधन की बढ़ती खपत के इस युग में उर्जा बचाने पर विचार किये बगैर पानी बचाने की दृष्टि में समग्रता का आना असंभव है। सोचिए, यदि गैस, ईंधन व बिजली जैसे स्रोत ही नहीं होंगे तो हमारी गाड़ियां, ट्यूबवेल, रसोईं के स्टोव कैसे चलेगे?

हकीकत यही है कि पानी के बिना न बिजली बन सकती है और न ही ईंधन व दूसरे उत्पाद बनानेवाले ज्यादातर उद्योग चल सकते हैं। किसी भी संयंत्र को ठंडा करने तथा कचरे का शोधन करने के लिए पानी चाहिए ही। कोयले से बिजली बनानेवाले थर्मल पॉवर संयत्रों में इलेक्ट्रिक जनरेटर को घुमाने के लिए जिस भाप की जरूरत पड़ती है वह पानी के बिना कहां संभव है? परमाणु उर्जा संयत्र 25 से 60 गैलन पानी प्रति किलोवाट घंटा की मांग करता है। तेल को साफ करके पेट्रोल बनाना बिना पानी के संभव नहीं है। बायो डीजल भी क्या बिना पानी के संभव है?

पानी बचाने के लिए उर्जा बचाने का यह नजरिया मुख्यरूप से अमेरिका में ही पनपा है लेकिन उनका यह नजरिया एक खास अनुभव के बाद आया है। यूनियन आफ कंसर्न सांइटिस्ट की एक रिपोर्ट बताती है कि बिजली बनाने में अमेरिका प्रतिदिन इतना ताजा पानी खर्च करता है जितना न्यूयार्क जैसे 180 शहर मिलकर एक दिन में खर्च करते हैं। यह आंकड़ा 40 बिलियन गैलन प्रतिदिन का है। अमेरिका में पानी की कुल खपत का मात्र 5 प्रतिशत उद्योग में, 13 प्रतिशत घरेलू उपयोग में,

37 प्रतिशत खेती में, 5 प्रतिशत अन्य कामों में और सबसे ज्यादा 41 प्रतिशत उर्जा के उत्पादन में खर्च होता है। एक ओर उर्जा के उत्पादन में ताजे पानी का खर्च बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ किसान उद्योग और शहर के बीच की खपत व बंटवारे के विवाद बढ़ रहे हैं। आंकलन यह है कि कम होती बारिश व सूखा मिलकर 2025 तक लास वेगास, साल्ट लेक, जार्जिया, टेनेसी जैसे इलाकों के पानी प्रबंधन पर लाल निशान लगा देंगे। चेतावनी यह भी है कि 2050 तक कोलरेडो जैसी कई प्रमुख नदी के प्रवाह में भी 20 प्रतिशत की कमी आयेगी।

बिजली उत्पादन के लिए इस्तेमाल होने वाले इन संयंत्रों से जो गरम पानी बाहर आता है उससे पूरा जैविक तंत्र प्रभावित होता है। पानी की शुद्धता के लिए जरूरी मछलियां व अन्य जीव तथा वनस्पति नष्ट हो जाते हैं। आसपास की मिट्टी की गुणवत्ता भी खत्म होती है और खेती भी प्रभावित होती है। इतना ही नहीं थर्मल पॉवर प्लांट से निकलने वाले आर्सेनिक, पारा, सीसा जैसे खतरनाक रसायन पूरे जीवन चक्र को बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। अमेरिका के थर्मल पॉवर प्लांट से 120 मिलियन टन कचरा छोड़ने का आंकड़ा है। भारत की सरकार ऐसे आंकड़ों को शायद ही कभी सार्वजनिक करे। खैर, इस पूरे परिदृश्य का परिणाम यह है कि 2004 के बाद से अब तक अमेरिका के 12 बड़े बिजलीघर बंद हो चुके हैं। अमेरिका के कई राज्यों में बांधों का बंधन ही खत्म कर दिया गया है।

पानी से बिजली बनाने की योजनाओं के मामले में भारत की पनबिजली परियोजनाएं पानी की मार झेल रही हैं। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के मुताबिक भारत की 89 प्रतिशत पनबिजली परियोजनाएं अपनी स्थापना से कम बिजली उत्पादन कर रही हैं। सैंड्रप के अनुसार टिहरी की क्षमता 2400 मेगावाट है लेकिन व्यवहार में वह औसतन 436 मेगावाट बिजली उत्पादन ही कर रही है। टिहरी में आज तक अधिकतम उत्पादन 700 मेगावाट से अधिक कभी नहीं हुआ। वाष्पन, गाद निकासी, मलवा निष्पादन और कुप्रंबधन को देखें तो पनबिजली परियोजनाएं लाभ का सौदा कम ही रहती हैं। बावजूद इसके विकास के नये पैमनों पर अमेरिका के नजीर के रूप में पेश करनेवाले हमारे नेता अफसर, योजनाकार और खुद नागरिकों ने अमेरिका और खुद के अनुभवों से कुछ नहीं सीखा।

नेता, अफसर और योजनाकार भले ही कुछ सीखें न सीखें लेकिन हमारे शहरी समाज को अमेरिका से कम से कम एक बात जरूर सीख लेनी चाहिए कि अगर वे पानी बचाना चाहते हैं तो उन्हें बिजली बचत का संकल्प लेना पड़ेगा। ❑

:: सूचना ::

स्वदेशी पत्रिका सम्राज्यवाद के खिलाफ एक सशक्त आवाज है। पत्रिका को ऐसे लोगों से प्रतिक्रियाएं, रिपोर्ट या आलेख की अपेक्षा है जो राष्ट्रहित में सोचते हैं और देश के स्वावलम्बन के लिए कुछ करने की इच्छा रखते है। जरूरी नहीं कि आप पत्रकार या लेखक ही हों, अपने आसपास से जुड़ी चीजों के प्रति आपकी संवदेना है और आप शब्दों में उसे लिख सकते है तो हमें अवश्य लिख भेजें। साथ ही स्वदेशी पत्रिका में छपे लेख आपको कैसे लगते हैं, क्या आप इसमें कुछ नए विषयों का समायोजन चाहते हैं कृपया हमें अवश्य अवगत कराएं। आपके विचारों को हम प्राथमिकता के साथ प्रकाशित करने का भी प्रयास करेंगे।

हमारा पता है :–

संपादक

स्वदेशी पत्रिका

'धर्मक्षेत्र', सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

कब रुकेगी कैंसर एक्सप्रेस

हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर पर कैंसर रोगी दर प्रति लाख 71 है, वहीं पंजाब के मालवा इलाके में यह आंकड़ा 125 से भी आगे पार कर चुका है। पंजाब में कैंसर के इस आंकड़ें को देखकर ऐसा कह सकते है कि जिस तरह सिंधु घाटी की महान सभ्यता प्राकृतिक आपदाओं की वजह से नेस्तनाबूत हो गयी, अब आधुनिक सिंधुघाटी का वही इलाका इंसानी वजहों से उत्पन्न कैंसर रूपी दानव से एक बार फिर बर्वादी के कगार पर है।

■ अखिलेश अखिल

पंजाब के उपजाये गेंहू चावल ने भले ही देश को सौगात में अन्न क्रांति दे दी हो लेकिन पंजाब इस इस क्रांति की बड़ी भारी कीमत चुका रहा है। जिस जमीन ने कभी सोने जैसा गेहूं पैदा किया था वही जमीन अब इतनी जहरीली हो गई है कि स्थानीय निवासियों को कैंसर की सौगात दे रही है। वैसे तो पूरे पंजाब पर कैंसर का खतरा देश के औसत से ज्यादा है लेकिन यहां भी मालवा का इलाका ऐसा है जो अब यहां से गुजरनेवाली कैंसर एक्सप्रेस के लिए पहचाना जाने लगा है। रोज रात इस इलाके से गुजरनेवाली कैंसर एक्सप्रेस का सफर बीकानेर पहुंचकर खत्म हो जाता है लेकिन क्या कैंसर एक्सप्रेस इसी तरह रोज पंजाब के कैंसर पीड़ितों को बीकानेर लाती ले जाती रहेगी, या इसका सफर कभी रुकेगा भी?

हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर पर कैंसर रोगी दर प्रति लाख 71 है, वहीं पंजाब के मालवा इलाके में यह आंकड़ा 125 से भी आगे पार कर चुका है। पंजाब में कैंसर के इस आंकड़ें को देखकर ऐसा कह सकते है कि जिस तरह सिंधु घाटी की महान सभ्यता प्राकृतिक आपदाओं की वजह से नेस्तनाबूत हो गयी, अब आधुनिक सिंधुघाटी का वही इलाका इंसानी वजहों से उत्पन्न कैंसर रूपी दानव से एक बार फिर बर्वादी के कगार पर है।

खेती के बदलते ढंग, रहन सहन से लेकर खान पान में आए बदलाव और धन व पैसों के प्रति बढते लोभ और लालच की वजह से सिंधुघाटी की इस नायाब धरती को कैंसर नामक जानलेवा बीमारी एकबार फिर निगलने को तैयार है। कैसे कोई बीमारी पैर से सिर तक पहुंचता है और फिर जानलेवा हो जाता है पंजाब इसका जीता जागता उदाहरण है। पहले पंजाब के मालवा इलाके में कैंसर का दंश और बाद में पूरे पंजाब में कैंसर के प्रकोप को देखते हुए आप कह सकते हैं कि इस अति विकसित राज्य को निगलने के लिए इतिहास फिर अपनी कहानी लिखने को तैयार है।

दरअसल पंजाब का भूगोल तीन इलाकों में बंटा हुआ है– मालवा, दोआब और मांझा। दोआब और माझा जिसे गेहूं और गन्ने की खेती के लिए जाना जाता है वहीं मालवा इलाका कपास की खेती में देश के कई राज्यों को पछाड़ता आ रहा है। आज से 20 साल पहले यहां देशी तरीके से कपास की खेती शुरू की गई थी लेकिन अब बीटी काटन के आने के बाद खेती के तरीके बदले तो किसानों की जिंदगी भी बदली और उनकी लाइफ स्टाईल भी। पूरे पंजाब में कपास की खेती 5.65 लाख हेक्टेयर की खेती होती है जबकि सिर्फ भटिंडा में 1.65 लाख हेक्टेयर की कपास खेती होती है।

कपास की इस खेती ने लोगों को आर्थिक रूप से संपन्न तो किया लेकिन अब यही संपन्नता लोगो की बलि मांग रही हैं। इसे आप विकास का साइड इफेक्ट भी कह सकते हैं। कैंसर के रूप में जो मौतें पूरे पंजाब में हो रही है और जिस तेजी से गांव के गांव कैंसर रूपी महामारी की चपेट में आते जा रहे हैं उससे यही लगता है कि समय रहते इसे रोकने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई सार्थक अभियान नहीं चलाए गए तो पंजाब का नामों निशान मिट जाएगा।

यहां का पूरा वातावरण ही जहरीला हो गया है। वातावरण में टाक्सिन इतने बढ़ गए है कि इसे अब रोक पाना सरकार के बूते की बात नहीं है। पंजाब में 18 फीसदी पेस्टीसाइड का प्रयोग होता है। ऐसे में जमीन की क्या स्थिति है आप खुद देख रहे हैं । जब तक बातावरण में फैले जहर को हम कम नहीं करेंगे बीमारी बढ़ती ही जाएगी।

कैंसर से आहत पंजाब को उसकी पुरानी खेती पद्धति और विरासत को लौटाने के लिए खेती विरासत मिशन के तहत काम कर रहे उमेंद्र दत्त कहते हैं कि पंजाब के हालात इतने खराब हो गए हैं कि – 'कहना मुश्किल है। पंजाब के पूरे वातावरण में विशाक्त तत्व आ गए हैं जिससे यहां के स्वास्थ्य और भोजन श्रृंखला ध्वस्त हो गए हैं। यहां के वायुमंडल में भी जहर है और भोजन में भी। खेती में जिस तरीके से और जितनी मात्रा में रसायनों का प्रयोग होता है उससे पूरा इकोतंत्र ही लड़खड़ा गया है। मामला केवल आदमी में फैल रहे कैंसर तक का ही नहीं है,पशुओं में भी बड़े पैमाने पर कैंसर के अलावा घातक बीमारियां घर कर गई है। जाहिर है यहां का दूध भी जहरीला होता गया है। धरती के नीचे का पानी पूरी तरह से जहरीला हो गया है और खेत की जमीन भी। ऐसे में इंसान के बचने

का रास्ता क्या बचा है कह नहीं सकता। सरकार घोषणा के अलावा कुछ करती नहीं, ऐसे में इस समाज को बचा पाना मुश्किल है।'

उमेंद्र दत्त की चिंता पंजाब के भविष्य को लेकर हैं क्योंकि जो वर्तमान है वह अभिशप्त है। कैंसर के कारण अधिकतर लोगों की रखी पूंजी समाप्त हो गई है। और इलाज के लिए 70 फीसदी लोगों को अपना कुछ न कुछ बेचना पड़ रहा है। इलाके के 9 फीसदी लोग ऐसे हैं जो कर्ज लेकर इलाज करा रहे हैं और 8 फीसदी ऐसे कैंसर रोगी हैं जिन्होने इलाज के लिए अपनी एफडी तोड़वायी है।

आइए आपको भटिंडा रेलवे स्टेशन से बीकानेर जाने वाले लोगो से मिलवाते हैं। हर रात 9 बजे अबोहर से बीकानेर के लिए ट्रेन जाती है। स्थानीय लोग इसी ट्रेन को कैसर एक्सप्रेस कहते हैं। 12 बोगियों वाली यह ट्रेन भटिंडा, मुख्तसर, मनसा, फिरोजपुर, मोंगा, बरनाला, फरीदकोट और संगरूर जिले के कैंसर रोगियों को बीकानेर तक पहुंचाती हैं। खचाखच भरे इस ट्रेन को आप देंखेंगे तो परेशान हो जाऐंगे। बच्चों से लेकर बूढ़े रोगी कराहते नजर आऐंगे। बीकानेर में कैंसर अस्पताल है और वहां रोगियों के ठहरने के लिए धर्मशाला और सराय है। इलाज भी सस्ता और रहने का इंतजाम भी सस्ता। गरीब लोग इसी ट्रेन से यात्रा करते हैं। भटिंडा से बीकानेर जाने में 54 रूपये किराया है जबकि भटिंडा में किसी भी प्राइवेट अस्पताल में घुसने का फीस 500 से कम नहीं है। ट्रेन की बोगी में सर्वजीत कौर से हमारी मुलाकात हुई। 40 साल की सर्वजीत कौर को ब्रेस्ट कैंसर हैं। भटिंडा की रहने वाली सर्वजीत के साथ उसके पति अंसा सिंह हैं। अंसा सिंह कहते हैं कि 'तीन बार हम बीकानेर हो आए। इलाज चल रहा है। अब तो हमारे पास कुछ बचा भी नहीं है। पता नहीं यह इलाका किस शाप से ग्रसित है'। दीवान चंद की उम्र 62 साल है। मुख्तसर के हैं दीवान चंद। अब तक अपने इलाज पर एक लाख से ज्यादा लुटा चुके हैं। फायदा कुछ नहीं है। दीवानचंद हर माह बीकानेर का दौरा कर रहे हैं। इसी तरह मुख्तियार कौर, बलबीर कौर, सवान सिंह और सोमा रानी की अपनी अपनी कहानी है। 56 साल की सोमा रानी पति जीत सिंह के साथ साल भर से बीकानेर दौड़ रही है। सोमा कहती है कि सरकार के लोग कुछ कर नहीं रहे और पूरा पंजाब मरता जा रहा है।

भटिंडा की जमीन तो अधिक मात्रा में कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से जहरीली हुई है, लेकिन वहों के वातावरण और पर्यावरण में जो जहरीले अणु तैर रहे हैं उसे लेकर सरकार से ज्यादा पर्यावरणविद परेशान हैं। थटिंडा में अभी दो थर्मल पावर चल रहे हैं जबकि तीसरा थर्मल पावर मनसा के गोबिंदपुरा में तैयार हो रहा है। इसके अलावा एक फर्टिलाइजर कारखाना और एक रिफाइनरी है। इससे भी बड़े पैमाने पर जल और वायु प्रदूषण हो रहा है। भटिंडा के गुरूनानकदेव थर्मल पावर से हमेशा कोल राख निकलने से इलाके के लोगों का जीना मुहाल है। सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है । भटिंडा के सिविल सर्जन इकबाल सिंह कहते हैं कि– 'मालवा इलाके में कैंसर फैलने के कोई एक कारण नही है कीटनाशक के साथ ही अधिक अल्कोहल लेने से भी यह बीमारी फैल रही है इसके साथ ही पानी में यूरेनियम की मात्रा बढ गई है। खानपान में आए बदलाव और उसमें कार्बाइड की मात्रा बढ जाने से भी कैंसर मरीजों की संख्या बढ रही है।' आपको बता दें कि भटिंडा और मनसा मे 1996 से लेकर 2001 के बीच 5 मिलियन लीटर पेस्टीसाइड के इस्तेमाल हुए हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि इतनी मात्रा में जहर का प्रयोग होने से उस जमीन का क्या हुआ होगा ?

उमेंद्र दत्त की चिंता पंजाब के भविष्य को लेकर हैं क्योंकि जो वर्तमान है वह अभिशप्त है। कैंसर के कारण अधिकतर लोगों की रखी पूंजी समाप्त हो गई है। और इलाज के लिए 70 फीसदी लोगों को अपना कुछ न कुछ बेचना पड़ रहा है। इलाके के 9 फीसदी लोग ऐसे हैं जो कर्ज लेकर इलाज करा रहे हैं और 8 फीसदी ऐसे कैंसर रोगी हैं जिन्होने इलाज के लिए अपनी एफडी तोड़वायी है।

उधर, उमेंद्र दत्त कहते हैं कि 'मालवा इलाके समेत पूरे पंजाब में केवल कैंसर का ही भयावह असर नही है, इन इलाकों में बडे पैमाने पर चर्म रोग, जनन समस्या,मानसिक रोगों के साथ ही बड़े पैमाने पर आबर्सन के मामले भी आ रहे हैं। आत्महत्या के मामले अलग से । ये आबर्सन महिलाओं और पशुओं में एक साथ देखे जा रहे हैं। इन तमाम रोगों के लिए चंडीगढ पीजीआई और भाभा आटोमिक रिसर्च सेंटर के कई सर्वे भी आ चुके हैं जिसमें बताया गया है कि पानी में फ्लाराइड और पेस्टीसाईड के तत्व मिले हुए हैं जबकि यहां के भूजल में यूरेनियम है फिर भी सरकारी स्तर पर कोई काम नहीं हो रहा है। लगता है कि सरकार इसमें भी वोट की राजनीति देख रही है।' कैंसर के बढते प्रकोप को देखते हुए ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में पंजाब की समृद्ध विरासत को हम खो न दें। खेती विरासत मिशन से जुड़ी अमन जोत कौर कहती हैं कि जब तक केमिकल फ्री खेती नहीं होगी और हमारा भोजन परंपरागत नहीं होगा तब तक इस जानलेवा बीमारी को नहीं रोका जा सकता। यही वजह है कि हम गांव गांव जाकर लोगों को और खासकर महिलाओं को केमिकल फ्री किचेन गार्डेन की सलाह दे रहे हैं और इसका पंजाब में असर भी हो रहा है।❑

युवा पीढ़ी न बह जाए इस सैलाब में

हाल के वर्षो में नशे की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ी है। शराब को दूर–दूर के गांवों में फैलाने में विभिन्न सरकारों ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बड़ी भूमिका निभाई है। उन्होंने अपनी आय का महत्वपूर्ण स्रेत शराब के ठेकों की नीलामी को बना दिया है शराब की बिक्री से यदि सरकारी खजाने में अधिक पैसा जा रहा है तो राजनीतिक दलों, नेताओं व अधिकारियों के नाम बहुत सा अवैध धन भी इस प्रक्रिया में आ रहा है। इस स्थिति में आश्चर्य नहीं है कि शराब की बुराई को न्यूनतम करने की अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी से सरकारें निरंतर पीछे हट रही हैं

■ भारत डोगरा

चुनाव प्रचार के बीच विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा इस ओर बहुत कम ध्यान दिया गया है कि शराब की बढ़ती लत से देशवासियों को कैसे राहत दी जाए जबकि शराब की लत एक अनियंत्रित बुराई के रूप में देश समाज को खोखला करती जा रही है। यही कारण है कि इसके विरोध में जन–भावनाएं, विशेषकर

महिलाओं की भावनाएं देश में दूर–दूर तक उमड़ रही हैं।

यह कड़वी सच्चाई है कि हाल के वर्षो में शराब के नशे की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ी है और शराब को दूर–दूर के गांवों में फैलाने में विभिन्न सरकारों ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बहुत सक्रिय भूमिका निभाई है। हालांकि संविधान में विशेषकर राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में राज्य को शराब को नियंत्रित करने के लिए स्पष्ट भूमिका दी गई है, पर व्यवहार में ज्यादातर सरकारों का इसके विपरीत आचरण रहा है। उन्होंने अपनी आय का महत्वपूर्ण स्रेत शराब के ठेकों की नीलामी को बना दिया है। इसके अतिरिक्त वैध–अवैध दोनों तरह की शराब की बिक्री से जुड़ा भ्रष्टाचार भी इसकी बिक्री में तेज वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। शराब की बिक्री से यदि सरकारी खजाने में अधिक पैसा जा रहा है तो राजनीतिक दलों, नेताओं व अधिकारियों के नाम बहुत सा अवैध धन भी इस प्रक्रिया में आ रहा है। इस स्थिति में आश्चर्य नहीं है कि शराब की बुराई को न्यूनतम करने की अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी से सरकारें निरंतर पीछे हट रही हैं।

दूसरी ओर देश और दुनिया में इस तरह के अध्ययन सामने आ रहे हैं कि शराब से कितनी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक क्षति होती है। मौजूदा समय में महिलाओं में भी शराब का चलन बढ़ रहा है जो स्तन कैंसर की संभावना बढ़ाता है। गर्भावस्था में मां का अधिक शराब पीना शिशु और दूध पीने वाले नवजात शिशु के लिए गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है। इधर कुछ समय से भ्रम फैलाया गया है कि शराब की कम मात्रा में सेवन से हृदय रोग कम होने में सहायता मिलती है। लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल में चेताया है कि यह भ्रामक प्रचार व्यावसायिक हितों से अधिक प्रेरित है और इसमें वैज्ञानिक तथ्यों की भूमिका कम है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रवक्ता डा. हैन्स एम्बलाद ने स्पष्ट कहा है कि थोड़ी मात्रा में शराब की वकालत करना भी अनुचित है। वैसे प्रायः कई मामलों में देखा गया है कि थोड़े का बहाना करते–करते लोग न जाने कब अधिक मात्रा में पीने लगते हैं और शराब की अधिक मात्रा हृदय के लिए कितनी हानिकारक है, यह जग

जाहिर है। शराब केवल एक व्यक्ति के स्वास्थ्य को बर्बाद नहीं करती है वरन पूरे परिवार की तबाही का कारण बनती है। आर्थिक तंगहाली की स्थिति में शराब पर अधिक पैसा खर्च होने से भोजन, शिक्षा आदि के लिए जरूरी खर्च भी शराब की भेंट चढ़ जाता है। पारिवारिक कलह और हिंसा के मामले में शराब मुख्य कारक है। बहुत से तलाक व परिवार टूटने के मामले शराब से जुड़े होते हैं। बहुत सी दुर्घटनाएं शराब के नशे में होती हैं। खासकर सड़क दुर्घटनाओं का बड़ा कारण शराब है। शराब पीने वाले लोग सड़क दुर्घटनाओं में स्वयं तो मरते ही है, दूसरों को भी मारते हैं। नशे में मर्यादा का कोई ख्याल नहीं रहता, अतः यौन अपराध की आशंका भी शराब के नशे में अधिक हो जाती है। बहुत से यौन अपराध शराब के नशे में ही किए जाते हैं। जिसे नशे के लिए बार–बार पैसों की जरूरत होती है, वह इस कारण भी अपराध करता है।

शराब के कारोबार से बड़े माफिया लगे होते हैं जो भ्रष्टाचार और अपराध का मुख्य स्रोत हैं। यदि यह सब कुछ छोड़ कर देखा जाए तो पता चलेगा कि गंभीर बीमारियों, दुर्घटनाओं, परिवारों के टूटन, अपराधों आदि के माध्यम से देश की कितनी क्षति शराब करती है। तो फिर सरकारें शराब को आय का साधन क्यों मानती हैं? जितना वे शराब से कमाती हैं, क्या उससे कई गुणा अधिक क्षति शराब से देश को नहीं होती है। यूं देश के कई हिस्सों में नशा विरोधी आंदोलनों ने समाज पर गहरा असर डाला है। स्वार्थी तत्वों ने आंदोलनों को कुलचने की कई बार कोशिश की। कई बार आंदोलन लड़खड़ाये भी, लेकिन फिर नयी ऊर्जा के साथ उठ खड़े हुए। आज देश में शराब–विरोधी कई छिटपुट आंदोलन चल रहे हैं, जिसमें बहुत से आंदोलन शराब के ठेकों को गांव से हटाने से जुड़े हैं। इसके संदर्भ में एक मांग कई स्थानों पर यह भी रखी गई है कि यदि 50 प्रतिशत से अधिक गांववासी ठेके के विरुद्ध ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दें तो शराब का ठेका गांव से हटा देना चाहिए। यदि ज्ञापन पहले दे दिया जाए, तो गांव में इसका प्रवेश होना ही नहीं चाहिए।

प्रयास यह भी हो रहे हैं कि धार्मिक स्थलों व शिक्षण संस्थानों से शराब की दुकानों को दूर करने के निर्देशों का ठीक से पालन किया जाए। ऐसा ही एक प्रयास हाल में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में जन–स्वास्थ्य सहयोग ने आरंभ किया। यहां के नशा–मुक्ति प्रयासों में मुख्य स्थान समूह या ग्रुप की भूमिका को दिया जाता है। जब कार्यकर्ताओं ने नशा–विरोधी प्रयास आरंभ किए नशे के आदी लोगों ने कहा कि अब हम इसे छोड़ना चाहते हैं पर छोड़ नहीं पा रहे हैं। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने उन्हें प्रोत्साहित किया व सहायता दी कि नशा करने वाले व्यक्ति अपने समूह बनाएं। इन समूहों के सदस्य एक–दूसरे से अपना दुख–दर्द ही नहीं बांटते हैं, नशा छोड़ने का निश्चय भी दृढ़ता से करते हैं। इन ग्रुप में शामिल ज्यादातर नशे के आदी लोगों ने नशा छोड़ने में सफलता प्राप्त की है। हालांकि कई ने ग्रुप में आने के बावजूद अपनी कमजोरी नहीं छोड़ी पर ऐसे लोगों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। ऐसे व्यक्ति फिर से नशा छोड़ने की राह पर आ सकें, इसके प्रयास भी चलते रहते हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रवक्ता डा. हैन्स एम्बलाद ने स्पष्ट कहा है कि थोड़ी मात्रा में शराब की वकालत करना भी अनुचित है। वैसे प्रायः कई मामलों में देखा गया है कि थोड़े का बहाना करते–करते लोग न जाने कब अधिक मात्रा में पीने लगते हैं और शराब की अधिक मात्रा हृदय के लिए कितनी हानिकारक है, यह जग जाहिर है।

वास्तव में नशामुक्ति आंदोलन में इतना नैतिक बल होना चाहिए कि सरकार कोई मांग माने या न माने, आंदोलन की नैतिक शक्ति से प्रभावित होकर ही गांव के नशेबाज नशा छोड़ने के लिए आगे आने लगे। यही नशा विरोधी आंदोलन की सबसे बड़ी सफलता है। आजादी की लड़ाई के दौरान यह नैतिक शक्ति दिखायी देती थी। सोनीपत, कुरुक्षेत्र (हरियाणा), रायपुर, दुर्ग, महासमुंद (मध्य प्रदेश), वेल्लोर (आंध्र प्रदेश), सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) कुमाऊं व गढ़वाल (उत्तराखंड) आदि क्षेत्रों में हुए शराब विरोधी आंदोलनों में भी यह नैतिक शक्ति देखी गई है।

शंकर गुहा नियोगी का उज्ज्वल उदाहरण हमारे सामने है जिनके नेतृत्व में शराब विरोधी आंदोलन के समय हजारों श्रमिकों ने शराब का नशा इसी नैतिक भावना से प्रेरित होकर छोड़ा व अपने संगठन द्वारा दिये गये क्षेत्रीय रचनात्मक कार्य में जुट गये। यह भी जरूरी है कि गांव में नशा–विरोधी समिति को स्थायी समिति के रूप में स्थापित किया जाए। जब गांव से शराब का ठेका हटाने का आंदोलन सफल हो जाए तो भी यह समिति पहले की तरह सक्रिय बनी रहे। इसकी बैठकें नियमित होती रहें। जो लोग अब तक नशा नहीं छोड़ सके हैं, उनकी लत छुड़वाने का प्रयास यह समिति करती रहे। यदि इस तरह स्थाई तौर पर किसी भी गांव में नशा विरोधी समिति ईमानदारी न निष्ठा से कार्य करेगी तो उससे नशा दूर करने में बहुत सहायता मिलेगी। ❑

हमारे बाजारों पर चीन का बढ़ता वर्चस्व

देश के कोने–कोने में स्थित बाजारों में चीन में उत्पादित वस्तुओं का ढेर लग गया है। चाइनीज विद्युत बल्ब झालर, चाइनीज रेडिमेड वस्त्र, चाइनीज खिलौने, चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद और तरह–तरह के कई अन्य चीनी उत्पाद भारतीय उद्योगों पर बुरा असर डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। यदि हम भारत–चीन के विदेश व्यापार परिदृश्य को देखें तो पाते हैं कि चीन से भारत का आयात बढ़ता गया, लेकिन भारत चीन को उतनी तेजी से निर्यात नहीं बढ़ा पाया।

■ जयंतीलाल भंडारी

पिछले महीने पेइचिंग में भारत और चीन के बीच रणनीतिक आर्थिक वार्ताओं के तीसरे दौर की बैठक में योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह आहलूवालिया ने कहा कि भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार में बढ़ता असंतुलन भारत के लिए चिंता का विषय बन गया है। भारत ने चीन के साथ विदेश व्यापार में तेजी से बढ़ते भारी घाटे को अव्यावहारिक बताते हुए भारत से चीन को कुछ और वस्तुओं का निर्यात बढ़ाकर व्यापार घाटे में कमी लाने की आवश्यकता प्रतिपादित की। यह भी उल्लेखनीय है कि दोनों देश वर्ष 2015 तक द्विपक्षीय कारोबार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने पर सहमत हुए हैं। भारत तथा चीन के बीच मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को लेकर वार्ता शुरू किए जाने की संभावनाएं भी आगे बढ़ी हैं। निसंदेह भारत के लिए चीन के साथ व्यापार असंतुलन की चिंताएं और बढ़ गई हैं।

भारत–चीन व्यापार के नवीनतम आंकड़े बता रहे हैं कि वित्त वर्ष 2013–14 में भारत के चीन निर्यात में कमी आई है और आयात तेजी से बढ़े हैं। पिछले वर्ष भी चीन को कुल 13.53 अरब डॉलर का निर्यात हुआ, जबकि आयात 52.24 अरब डॉलर का हुआ। इस तरह व्यापार घाटा लगभग 39 अरब डॉलर का रहा। जबकि वित्त वर्ष 2011–12 में यह व्यापार घाटा 37 अरब डॉलर का था। एक ओर जहां चीन भारत का चौथा सबसे बड़ा कारोबारी साझीदार है, वहीं दूसरी ओर चीन के साथ बहुत तेजी से बढ़ता व्यापार घाटा भारतीय विदेश व्यापार और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भारी चिंता का विषय है। स्थिति यह है कि देश के कोने–कोने में स्थित बाजारों में चीन में उत्पादित वस्तुओं का ढेर लग गया है। चाइनीज विद्युत बल्ब झालर, चाइनीज रेडिमेड वस्त्र, चाइनीज खिलौने, चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद और तरह–तरह के कई अन्य चीनी उत्पाद भारतीय उद्योगों पर बुरा असर डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। यदि हम भारत–चीन के विदेश व्यापार परिदृश्य को देखें तो पाते हैं कि चीन से भारत का आयात बढ़ता गया, लेकिन भारत चीन को उतनी तेजी से निर्यात नहीं बढ़ा पाया।

गौरतलब है कि वर्ष 2000 से भारत–चीन व्यापार में भारी उछाल आया है। भारत और चीन ने नाथुला दर्रा से होकर 6 जुलाई, 2006 से सीमावर्ती व्यापार बहाल करने के ऐतिहासिक समझौते को कार्यान्वित किया है। पिछले वर्ष के अक्टूबर माह में प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की चीन यात्रा के दौरान भारत की सोच यह थी कि सीमा मुद्दों के साथ–साथ आर्थिक मुद्दे बातचीत में प्रमुख रहेंगे, लेकिन वार्ता में आर्थिक मुद्दे प्रमुख नहीं रहे। भारत–चीन व्यापार के तहत व्यापार क्योंकि असंतुलन स्पष्ट दिखाई दे

रहा है, इसलिए इस बात को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने चीनी नेतृत्व के समक्ष पुरजोर ढंग से उठाया। लेकिन चीन भारत से आयात बढ़ाने के लिए तत्काल कोई प्रत्यक्ष पहल करने के लिए तैयार नहीं हुआ है। भारत–चीन के बीच हुए एमओयू के तहत चीन ने भारत के कई उत्पादों के आयात के लिए अपने दरवाजे खोलने पर सहमति दी है। लेकिन वास्तविक व्यापार परिदृश्य पर चीन के द्वारा कदम–कदम पर मुश्किलें निर्मित की जा रही हैं। भारत दो वर्ष पहले तक चीन को बड़ी मात्रा में समुद्री उत्पादों का निर्यात करता था, लेकिन चीन से कुछ प्रतिबंध के कारण इस निर्यात में काफी गिरावट आई है। भारत को चीन में दवाइयों के निर्यात में भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। पेट्रोलियम उत्पाद, अयस्क, खनिज, प्लास्टिक डाई और अन्य उत्पादों के निर्यात के लिए चीन में टैक्स और बाजार संबंधी मुद्दे हैं। खाद्य तेल का व्यापार चीन में प्रतिबंधित है। जहां चीन में भारतीय उत्पादों पर लगाए गए प्रतिबंध भारत की चिंता बढ़ा रहे हैं, वहीं नवम्बर 2013 में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा जारी किए गए नए आर्थिक सुधारों और नई आर्थिक योजनाओं से भारत के समक्ष नई व्यापारिक चुनौती खड़ी हो गई है।

चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने नए आर्थिक सुधारों और नई आर्थिक योजनाओं का जो विस्तृत ब्योरा जारी किया है, उसमें ऐसे आर्थिक सुधार हैं जो पहले देखने को नहीं मिले हैं। स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि चीन लंबी अवधि के विकास को और नई व्यापार संभावनाओं को लेकर नए सिरे से आगे बढ़ने के लिए संकल्पित है। सुधारों के नए दस्तावेज में मुक्त बाजार की पेशकदमी, श्रमिकों के शिविरों को हटाने, जमीन के इस्तेमाल की अवधि में सुधार, सरकारी उद्यम, कराधान, प्रवासी कामगारों के अधिकार, भ्रष्टाचार विरोधी अभियान, ढांचागत अर्थव्यवस्था और आर्थिक–प्रशासनिक सुधार के संबंध में अभूतपूर्व प्रावधान हैं। सबसे बड़ा संकेत है निजी क्षेत्र और बाजार के लिए समर्थन। दस्तावेज में यह भी कहा गया है कि संसाधनों के आवंटन में बाजार को निर्णायक भूमिका दी जाएगी। सभी स्तरों पर कीमतों अथवा प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन में सरकार का हस्तक्षेप कम किया जाएगा। नए दस्तावेज का स्पष्ट इरादा विभिन्न बाजार विरोधी अनियमितताओं एवं विसंगतियों को दूर करते हुए आक्रामक रूप से निर्यात बढ़ाना भी है।

वस्तुतः हमें चीन के साथ व्यापार असंतुलन कम करने के लिए रणनीतिक प्रयास करने होंगे। हमें चीन से बहुतायत में आने वाली कई अनावश्यक वस्तुओं के आयात पर लगाम लगाना होगी। कई सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान व अन्य चीजों के आयात पर शुल्क लगाया जाना चाहिए, फिर शुल्क में बढ़ोतरी की जानी चाहिए। हमें उन सभी चीनी उत्पादों के आयात को भी नियंत्रित करना होगा जो भारत में मलेशिया रूट से आते हैं।

वस्तुतः हमें चीन के साथ व्यापार असंतुलन कम करने के लिए रणनीतिक प्रयास करने होंगे। हमें चीन से बहुतायत में आने वाली कई अनावश्यक वस्तुओं के आयात पर लगाम लगाना होगी। कई सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान व अन्य चीजों के आयात पर शुल्क लगाया जाना चाहिए, फिर शुल्क में बढ़ोतरी की जानी चाहिए। हमें उन सभी चीनी उत्पादों के आयात को भी नियंत्रित करना होगा जो भारत में मलेशिया रूट से आते हैं। हम चीन के बाजार को गंभीरता से लें और उन क्षेत्रों को समझें जहां चीन को भारत की दरकार है। भारतीय उत्पाद गुणवत्तायुक्त और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी होते हैं। इसलिए ऐसा कोई कारण नहीं है कि चीनी उपभोक्ता और कंपनियां इनकी खरीद नहीं कर सकते। चीन के साथ व्यापार घाटे को समाप्त करने के लिए भारत से चीन को विविध प्रकार के निर्यात बढ़ाने होंगे। खासतौर से चीन में प्रदूषण कानून सख्त होने से पर्यावरण से जुड़े कई उद्योगों की इकाइयां बड़ी संख्या में बंद हो गई हैं। ऐसे में भारत चीन के बाजार में ऑटो कम्पोनेंट, स्टेनलेस स्टील, इन्वर्टर, कॉटन यार्न, लेदर सामान आदि वस्तुओं का निर्यात तेजी से बढ़ाने की संभावना रखता है। इतना ही नहीं, भारत अपनी ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था, सूचना प्रौद्योगिकी, बायो टेक्नोलॉजी, फार्मा स्युटिकल, इंजीनियरिंग, मेडिकल एवं विज्ञान क्षेत्रों की विजय पताका चीन में भी फहरा सकता है।

हमें यह समझना चाहिए कि चीन धीरे–धीरे उच्च लागत वाली अर्थव्यवस्था का देश बनता जा रहा है और वहां श्रम व मजदूर की समस्याएं बढ़ गई हैं, जो चीन के बाजार को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे में चीन को निर्यात बढ़ाने के लिए भारत सरकार को अपने निर्यातकों को हरसंभव प्रोत्साहन देना होगा। चीन से व्यापार में मुकाबला करने के लिए भारत को कम लागत पर गुणवत्तापूर्ण उत्पादन करने वाले देश के रूप में पहचान बनानी होगी। चीन की तरह भारत को भी गुड गवन्रेंस की स्थिति बनानी होगी। ऐसे रणनीतिक प्रयासों से ही भारत–चीन के साथ व्यापार असंतुलन की चिंताओं को कम कर सकेगा। ❑

काले धन पर बेबस केन्द्र सरकार

'आर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनोमिक कार्पोरेशन एंड डेवलपमेंट' ने अप्रैल 2009 के शुरू में प्रकाशित लेखों–जोखों में उल्लेख किया था कि स्विस बैंकों समेत अन्य टैक्स हेवेंस में 25 लाख करोड़ से लेकर 70 लाख करोड़ की धनराशि है। जर्मनी के वित्त मंत्रालय ने एलटीजी बैंक से जो सूची प्राप्त की है उसमें करीब 100 भारतीयों के भी नाम शामिल हैं। संप्रग सरकार इन कर चोरों के नाम उजागर क्यों नहीं करती?

■ **बलवीर पुंज**

सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई एक जानकारी के जवाब में हाल में वित्त मंत्रालय ने बताया है कि इस समय सरकार के पास विदेशों में जमा भारतीयों के काले धन का कोई पुख्ता आंकड़ा नहीं है। वहीं विदेशी टैक्स पनाहगाहों में जमा काले धन को लेकर संप्रग सरकार के रवैये पर सर्वोच्च अदालत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए पिछले दिनों कहा है कि कालेधन की वापसी के लिए आपने सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश करने के अलावा कुछ नहीं किया। अदालत ने सरकार को फटकार लगाते हुए बताया कि यदि काला धन वापस आ जाए तो अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोत्तरी होगी और हम लोग जो टैक्स देते हैं उनमें 30 प्रतिशत की कमी आएगी।

काले धन को लेकर केन्द्र सरकार की बेबसी क्या है? विदेशों में जमा काले धन की वापसी को लेकर संप्रग सरकार प्रारंभ से ही ढुलमुल रवैया अपनाए हुए है। भारतीय जनता पार्टी जहां इस मुद्दे को गंभीरता से उठाती आई है वहीं कांग्रेस इसकी गंभीरता को कमतर साबित करने की कोशिश करती रही है। इस बार के कांग्रेस पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में काले धन पर विशेष दूत की नियुक्ति का वादा किया गया है। निरंतर हो रही आलोचना के कारण संप्रग सरकार इस बार काले धन को लेकर गंभीर होने का दिखावा कर रही है, किंतु काले धन की वापसी को लेकर संप्रग सरकार का रवैया अब तक जुबानी जमाखर्च का ही रहा है।

वस्तुतः 4 जुलाई 2011 को सर्वोच्च न्यायालय ने काले धन की वापसी और जांच की दिशा में उठाए जा रहे कदमों की निगरानी के लिए एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया था। अदालत ने सरकार द्वारा नियुक्त उच्च स्तरीय समिति को तुरंत एसआईटी से जुड़ने का भी आदेश दिया था। एसआईटी को सर्वोच्च न्यायालय को रिपोर्ट करना था। एसआईटी स्वीकार करने में सरकार द्वारा दिखाई जा रही अनिच्छा पर आपत्तिव्यक्त करते हुए जस्टिस एच.एल. दत्तू की अगुवाई वाली बेंच ने सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि सरकार के पास पहले से मौजूद मैकेनिज्म होने के कारण एसआईटी गठित करने की आवश्यकता नहीं है।

वास्तव में संप्रग सरकार को काले धन का मुद्दा गर्माने पर बोफोर्स का भूत फिर से सामने आने का खौफ सताता है। बोफोर्स दलाली में लूटी गई रकम स्विस बैंक में जमा थी। बोफोर्स दलाली में क्वात्रोची को 64 करोड़ का कमीशन मिला था। वाजपेयी के कार्यकाल में ब्रिटिश अधिकारियों से संपर्क कर इन खातों से धन निकालने पर रोक लगवाई गई थी, किंतु संप्रग के कार्यकाल में वह रोक हटवा दी गई, जिसके कारण क्वात्रोची दलाली का सारा धन निकाल पाने में सफल हुआ।

वास्तव में संप्रग सरकार को काले धन का मुद्दा गर्माने पर बोफोर्स का भूत फिर से सामने आने का खौफ सताता है। बोफोर्स दलाली में लूटी गई रकम स्विस बैंक में जमा थी। बोफोर्स दलाली में क्वात्रोची को 64 करोड़ का कमीशन मिला था। वाजपेयी के कार्यकाल में ब्रिटिश अधिकारियों से संपर्क कर इन खातों से धन निकालने पर रोक लगवाई गई थी, किंतु संप्रग के कार्यकाल में वह रोक हटवा दी गई, जिसके कारण क्वात्रोची दलाली का सारा धन निकाल पाने में सफल हुआ।

कालेधन और टैक्स हेवेंस को खत्म करने के लिए चल रहे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों को देखते हुए लालकृष्ण आडवाणी ने अप्रैल, 2007 में ही डॉ. मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर भारत के संबंध में समुचित कदम उठाने की अपील की थी। तत्कालीन वित्तमंत्री की ओर से जो जवाब आया उससे सरकार द्वारा कदम उठाने का संकेत मिला था। किंतु धन वापसी की प्रक्रिया प्रारंभ करने की जगह सरकार ने जर्मनी स्थित भारतीय राजदूत को पत्र लिखकर यह निर्देश दिया

कि स्विस बैंकों में काला धन रखने वाले भारतीयों का नाम उजागर करने के लिए जर्मनी सरकार पर दबाव नहीं डाला जाए। आखिर संप्रग सरकार किन चेहरों को बचना चाहती है?

अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंसियल इंटेग्रिटी के अनुमान के अनुसार भारत से प्रतिवर्ष 27 अरब डॉलर स्विस बैंक आदि में जमा कराया जाता है। 160 विकासशील देशों की सूची में भारत का स्थान पांचवाँ है। जीएफआई के अनुसार 2002 से 2006 के बीच भारत से औसतन 22.7 अरब से 27.3 अरब डॉलर प्रतिवर्ष कालाधन विदेशी बैंकों में जमा होता रहा। 'आर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनोमिक कार्पोरेशन एंड डेवलपमेंट' ने अप्रैल 2009 के शुरू में प्रकाशित लेखों–जोखों में उल्लेख किया था कि स्विस बैंकों समेत अन्य टैक्स हेवेंस में 25 लाख करोड़ से लेकर 70 लाख करोड़ की धनराशि है। जर्मनी के वित्त मंत्रालय ने एलटीजी बैंक से जो सूची प्राप्त की है उसमें करीब 100 भारतीयों के भी नाम शामिल हैं। संप्रग सरकार इन कर चोरों के नाम उजागर क्यों नहीं करती?

स्विट्जरलैंड की प्रमुख पत्रिका 'स्विजर इलस्ट्रीएते' ने 19 नवंबर, 1991 के अपने अंक में राजीव गांधी समेत तीसरी दुनिया के करीब दर्जन भर राजनेताओं के नामों का खुलासा किया था, जिन्होंने स्विस बैंकों में अपनी काली कमाई जमा कराई थी। केजीबी दस्तावेजों का उल्लेख करते हुए पत्रिका ने लिखा था कि राजीव गांधी की विधवा सोनिया गांधी अपने अवयस्क पुत्र के नाम पर उन गोपनीय खातों की देखरेख कर रही हैं, जिनमें 2.5 अरब स्विस फ्रैंक जमा हैं। इसके आलोक में 7 दिसंबर, 1991 को संसद में सीपीआई–एम के सांसद अमल दत्त ने नाम लेकर 2.2 अरब डॉलर का मामला उठाया था।

दूसरा खुलासा रूसी खुफिया एजेंसी–केजीबी के गोपनीय दस्तावेजों से हुआ था। येवजेनिया अल्बाट्स नामक एक खोजी पत्रकार ने अपनी पुस्तक – 'दि केजीबी एंड इट्स होल्ड इन रशियाः पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर' में इन दस्तावेजों के आधार पर गंभीर खुलासा किया है। अल्बाट्स ने उपरोक्त पुस्तक की पृष्ठ

संख्या 223 में लिखा है, 'केजीबी प्रमुख विक्टर चेबरीकोव के हस्ताक्षर वाले एक पत्र में पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी के पुत्र के साथ केजीबी के रिश्तों की बात दर्ज है। इसमें सोवियत व्यापार संघों के सहयोग से अपने नियंत्रण वाली फर्म को हो रहे व्यापारिक लाभ के लिए आर गांधी द्वारा आभार प्रकट करने का भी उल्लेख है। अल्बाट्स ने यह भी खुलासा किया है कि सन् 2005 में केजीबी प्रमुख विक्टर चेबरीकोव ने सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति से राजीव गांधी के परिजनों, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पाओला मैनो (सोनिया गांधी की मां) को अमेरिकी डॉलर में भुगतान करने की अधिकारिता देने को कहा था।

अल्बाट्स के खुलासे से भी पहले रूसी मीडिया ने दलाली का सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया था। उन खुलासों के आधार पर अंग्रेजी समाचार पत्र 'द हिंदू' ने 4 जुलाई, 1992 के अपने संस्करण में लिखा था, ''रूसी विदेशी खुफिया सेवा इस संभावना को स्वीकार करती है कि राजीव गांधी के परिवार की नियंत्रण वाली कंपनी को मुनाफे वाले सोवियत ठेके दिलाने में केजीबी ने मदद की होगी।''

क्या ये सभी आरोप गंभीर नहीं हैं? क्या ये मामले भारत के शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व और प्रजातांत्रिक व्यवस्था की प्रामाणिकता पर उंगली नहीं उठाते? यदि ये आरोप निराधार हैं तो इन आरोपों का अब तक खंडन क्यों नहीं किया गया? सोनिया गांधी या राहुल गांधी ने आज तक इन पत्र–पत्रिकाओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज कराया? कहीं इस खामोशी में छिपा राज ही काले धन की वापसी में अवरोध तो नहीं खड़ा कर रहा? ❑

भारतीय काल गणना की सार्वभौमिकता व खगोल शुद्धता

भारतीय काल गणना में मासों की रचना व नामकरण भी, वर्ष भर में आने वाली 12 पूर्णिमाओं के नक्षत्रों को दृष्टिगत रखकर पूर्ण वैज्ञानिकता के आधार पर किया गया है। यथा चित्रा नक्षत्र में पूर्णिमा वाले मास का नामकरण चैत्र, विशाखा में पूर्णिमा वाले मास का नाम वैशाख, ज्येष्ठा नक्षत्र में पूर्णिमा वाले मास का ज्येष्ठ, उत्तराषाढ़ा में पूर्णिमा वाले मास का आषाढ़, श्रवण नक्षत्र में पूर्णिमा आने पर श्रावण, अश्विनी में पूर्णिमा आने पर अश्विन और इसी प्रकार फाल्गुन पर्यन्त बारह मासों के नाम उन मासों की पूर्णिमा वाले दिन के नक्षत्र के अनुसार निर्धारित किये गये हैं।

■ डॉ. भगवती प्रकाश

विश्व में प्रचलित सभी काल गणनाओं में भारतीय तिथियाँ ही सार्वभौम सन्दर्भ योग्य दिनक्रम प्रदान करती हैं। इन तिथियों का आरम्भ व समाप्ति काल पृथ्वी पर सभी स्थानों पर एक समान होने से उनका सन्दर्भ सार्वभौम होता है। दूसरी ओर आंग्ल तारीखें मध्य रात्रि से बदलती हैं जिसका (मध्य रात्रि का) समय स्थान विशेष पर अलग–अलग होता है व भिन्न–भिन्न स्थानों पर उसमें 24 घण्टे तक का अन्तर आ जाता है। उदाहरणतः भारत व अमरीका में मध्य रात्रि में साढ़े

बारह घण्टे तक का अन्तर होने पर भी हिन्दू कालमान की तिथियों में परिवर्तन तो एक ही समय होता है। लेकिन, तारीख बदलने में सदैव 12 घण्टे 30 मिनट तक का अन्तर आ जाता है, और अन्तर्राष्ट्रीय तारीख रेखा के पूर्व एवं पश्चिम में तो तारीखों में सदैव ही एक दिन का अन्तर रहता है। भारतीय तिथियों की दृष्टि से यदि अभी ईस्वी सन् 2014 के हिन्दू नववर्ष के प्रथम दिन का ही विचार करें तो, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा (एकम) का प्रवेश रविवार, मार्च 30 को भारत में मध्य रात्रि के बाद, मार्च 31 प्रारम्भ हो जाने के 14 मिनट (अर्थात रात्रि 12 बजकर 14 मिनट) पर होगा। इस समय पृथ्वी पर चाहे कहीं रात्रि हो या दिन, अथवा प्रातःकाल हो या सायंकाल, चैत्र शुल्क प्रतिपदा उसी समय, सभी स्थानों पर एक साथ प्रारम्भ होगी। इस क्रम में सोमवार, मार्च 31 को रात्रि में 10 बजकर 27 मिनट पर चाहे कही दिन हो या रात अथवा प्रभात हो या सायंकाल, प्रतिपदा समाप्त हो कर द्वितीया भी एक साथ ही प्रारम्भ होगी। इसी अनुरूप मंगलवार, अप्रैल 1, 2014 को रात्रि 9.11 बजे तृतीया प्रारम्भ हो जायेगी। सम्पूर्ण पृथ्वी पर हिन्दू कालमान की तिथियों का परिवर्तन समसामयिक (एक साथ व एक ही समय) होने से ये तिथियाँ अन्तर्राष्ट्रीय सन्दर्भ के लिये सर्वाधिक उपयुक्त हैं। यथाः यदि, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन भारत से भेजे किसी फेक्स या ईमेल में या अन्य भी किसी घटना के सन्दर्भ में भारतीय समयानुसार उस दिन, 31 मार्च 2014 को प्रातः 7 बजे का समय देना है तो भारत में रात्रि 12 बजकर 14 मिनट पर जब प्रतिपदा प्रारम्भ होती है उसके 6 घण्टे 44 मिनट बाद का समय होने से यदि, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के प्रवेशोपरान्त 6 घण्टे 44 का सन्दर्भ दे दिया जाये तो वह सर्वाभौम सन्दर्भ बन जायेगा, जिसका निर्वचन, व्याख्या या सन्दर्भ सर्वत्र समान रूप से व तत्काल बोधगम्य हो जायेगा।

दूसरी ओर यदि आंग्ल तारीख को सन्दर्भित कर यह लिखा जाये कि मार्च 31, 2014 को भारतीय समयानुसार प्रातः 7 बजे, तो उस समय अमेरिका में 30 मार्च सायंकाल 6.30 बजे का समय होगा, इग्लैण्ड में 30 मार्च का मध्य रात्रि 1.30 का समय होगा, बेकर द्वीप पर 30 मार्च का मध्यान्ह 1.30 का समय व थाइलैण्ड में 31 मार्च का प्रातः 10.30 बजे का सन्दर्भ आयेगा। यह अत्यन्त उलझाने वाला होता

है।

हिन्दू काल गणना की ये तिथियाँ, सूर्य व चन्द्रमा के बीच प्रति 12^0 कोणीय दूरी बढ़ने या घटने पर एक–एक कर बदलती हैं। पृथ्वी पर कही से भी चन्द्रमा व सूर्य के बीच की कोणीय या चापीय दूरी नापी जाये, वह सदैव एक समान ही दिखलायी देती है या नापने में आती है। अतएव सम्पूर्ण भू – मण्डल पर प्रत्येक हिन्दू तिथि एक साथ या एक ही समय परिवर्तित होती है। दूसरी ओर चन्द्रोदय में भी स्थान भेद से एक दिन तक का अन्तर होने से अरब हिजरी तिथियों में भी विविध स्थानों की तिथियों व पर्वों या त्यौहारों में एक दिन तक का अन्तर आ जाता है। हिन्दू गणनाओं के अन्तर्गत सम्पूर्ण भू–मण्डल पर अमावस्या का आरम्भ व अन्त एक ही समय होता है, उसमे 1 मिनट का भी अन्तर स्थान भेदवश नहीं आता है। तिथियों में अमावस्या को सूर्य व चन्द्रमा एक ही रेखांश पर होते हैं। वहाँ से उनके (सूर्य व चन्द्र के) बीच कोणीय अन्तर 12^0 तक होने तक शुक्ल प्रतिपदा रहती है व 12^0 से 24^0 होने तक द्वितीया, 24^0 से 36^0 कोणीय दूरी होने तक तृतीया व इसी प्रकार 168^0–180^0 के बीच पूर्णीमा व उसके बाद 180^0–192^0 तक कृष्ण प्रतिपदा। पृथ्वी से सूर्य व चन्द्र की दूरी इतनी अधिक है कि सूर्य व चन्द्रमा के बीच की कोणीय दूरी कही से भी नापने पर वह एक समान ही दिखायी देती है।

भारतीय काल गणना में मासों की रचना व नामकरण भी, वर्ष भर में आने वाली 12 पूर्णिमाओं के नक्षत्रों को दृष्टिगत रखकर पूर्ण वैज्ञानिकता के आधार पर किया गया है। यथा चित्रा नक्षत्र में पूर्णिमा वाले मास का नामकरण चैत्र, विशाखा में पूर्णिमा वाले मास का नाम वैशाख, ज्येष्ठा नक्षत्र में पूर्णिमा वाले मास का ज्येष्ठ, उत्तराषाढ़ा में पूर्णिमा वाले मास का आषाढ़, श्रवण नक्षत्र में पूर्णिमा आने पर श्रावण, अश्विनी में पूर्णिमा आने पर अश्विन और इसी प्रकार फाल्गुन पर्यन्त बारह मासों के नाम उन मासों की पूर्णिमा वाले दिन के नक्षत्र के अनुसार निर्धारित किये गये हैं। आंग्ल मासों में तो ज्यूलियस सीजर ने एक मास का नाम अपने नाम पर जुलाई कर दिया तो उसके भतीजे अगस्टस ने सम्राट बनने पर 'सेक्सटिनिल' नामक छठे मास का नाम अपने नाम पर अगस्त कर लिया। जुलाई में 31 दिन होते थे तो उसने भी 'मैं किसी से कम नहीं' के भाव से अगस्त में भी 30 के स्थान पर 31 दिन करवा दिये। इसके लिये फरवरी में तब 29 दिन होते थे, वे घटा कर 28 करवा दिये। रोमन सम्राट क्लाडियस ने भी मई मास का नाम परिवर्तन करा कर अपने नाम पर क्लाडियस और नीरो ने अप्रेल मास का नाम अपने नाम पर नीरोनियस भी करवा लिया था। लेकिन, ये नाम अधिक दिन नहीं चल पाये और वापस अप्रेल व मई के नाम से ही सम्बोधित किये जाने लगे। हिन्दू मासों के नाम के प्रणेता ऋषियों ने इन सभी मासों के नाम खगोलीय संयोग के अनुरूप चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद आदि भी इन मासों की पूर्णिमाओं के नक्षत्रों के अनुसार भी पिछले 1000 वर्षों में तब ही किये, जब इन महीनों की पूर्णिमाएँ इन नक्षत्रों में आने लगी थीं। वस्तुतः प्रति 25,765 वर्षों में अयन चलन की एक आवृत्ति पूरी होती है। अयन चलन वस्तुतः पृथ्वी के घूर्णन की धुरी में, अन्य ग्रहो के आकर्षण के कारण आने वाला लघु वृत्ताकार विचलन है, और इसी कारण प्रतिवर्ष बसन्त सम्पात कुछ विकलाओं में पीछे सरकता जाता हैं। अयन चलन के कारण ही निरयन ग्रह गणनाओं में मकर सक्रान्ति 22 दिसम्बर से 14 जनवरी तक आगे बढ़ गयी है, और उसके बाद 15,16, व 17 जनवरी इसी क्रम में और आगे बढ़ती जायेगी। पाश्चात्य खगोलज्ञ आरम्भ में अयन चलन से अनभिज्ञ थे। लेकिन, अब उन्होने मान लिया है कि अयन चलन होता है व भारतीयों द्वारा प्रयुक्त अयन चलन का मान खगोल शुद्ध हैं। उस अयन चलन के कारण जब ये पूर्णिमायें चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा आदि मासों में आने लगी तब ही इस खगोलीय क्रम के अनुसार विद्वान ऋषियों ने खगोलीय घटना चक्र के अनुरूप मासों का चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ आदि नामकरण किया है। इससे पूर्व वेदिक काल में चैत्र, वैशाख आदि मासों के नाम मधु, माधव, शुक्र, नभ, नभस्य, इश, ऊर्जा, सह, सहस्य, तप, तपस्या आदि प्रचलित थे। इसीलिये प्राचीन यजुर्वेद वाजसानेयी संहिता और तैत्तिरीय संहिता आदि में मासों के यही नाम मधु माधव आदि मिलते हैं। यही कारण है कि रामचरित मानस में भी चैत्र मास में राम नवमी के दिन भगवान राम के जन्म के मास का नाम 'मधु' मास लिखा है यथाः

चार दाँत वाले हाथी 10 लाख वर्ष पूर्व विलुप्त हो गये, रामायण में उनका वर्णन आता है और हमारी काल गणनानुसार त्रेता युग, जिसमें श्री राम का जन्म हुआ था, उसकी अवधि 21,25,115 वर्षों से लेकर 8,69,115 वर्षों के बीच रही है, तो यह श्रीराम, श्रीमद्वाल्मिकीय रामायण और त्रेता युग के काल–मान का सर्वाधिक सटीक प्रमाणीकरण है। चूंकि चार दाँत वाले हाथी 10 लाख वर्ष पूर्व ही विलुप्त हो गये थे।

''नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पच्छ अभिजित हरि प्रीता'' इस चौपाई में चैत्र मास के स्थान पर वेदिक कालीन व रामायण कालीन मास–नाम मधु मास लिखा है।

चूंकि श्री राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था। भारतीय काल गणनानुसार वर्तमान में 4,32000 वर्षमान के कलियुग के 5115 वर्ष हुये हैं और उसके पूर्व 8,64,000 वर्षमान का द्वापर युग व्यतीत हुआ था, जिसके अन्त में और आज से 5240 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। द्वापर युग के पूर्व 12,96,000 वर्ष का त्रेता युग व्यतीत हुआ है, जिसके अन्तिम चरण में श्री राम का जन्म हुआ है। इस प्रकार त्रेता युग जो 8,69,115 वर्ष पूर्व समाप्त हो गया था। इसे लेकर आधुनिक इतिहासकार आक्षेप करते हैं कि, वर्तमान सृष्टि व सभ्यता ही इतनी प्राचीन नहीं है। महाभारत काल को वे ईसा से मात्र 1000 वर्ष प्राचीन व रामायण काल को वे ईसा से 1500 वर्ष प्राचीन ही ठहराते हैं। जबकि रामायण में वाल्मिकी जी ने जिन 4 दाँत वाले हाथियों का वर्णन किया है। वैसे चार दाँत वाले हाथियों के 15–20 लाख वर्ष प्राचीन जीवाश्म व कंकाल आज बड़ी संख्या में उत्तरी अमेरिका, फ्रासं, जर्मनी, रूस, अफ्रीका व श्री लंका, पाकिस्तान आदि में आज मिल रहे हैं। पुरातात्विक उत्खननों के आधार पर आधुनिक पुरातत्वविद कहते हैं कि पृथ्वी पर ये 4 दाँत वाले हाथी 2.5 करोड़ वर्ष पहले से होते आये हैं और वे 10 लाख वर्ष पूर्व पूरी तरह से विलुप्त हो गये थे। यदि चार दाँत वाले हाथी 10 लाख वर्ष पूर्व विलुप्त हो गये, रामायण में उनका वर्णन आता है और हमारी काल गणनानुसार त्रेता युग, जिसमें श्री राम का जन्म हुआ था, उसकी अवधि 21,25,115 वर्षों से लेकर 8,69,115 वर्षों के बीच रही है, तो यह श्री राम, श्रीमद्वाल्मिकीय रामायण और त्रेता युग के काल–मान का सर्वाधिक सटीक प्रमाणीकरण है। चूंकि चार दाँत वाले हाथी 10 लाख वर्ष पूर्व ही विलुप्त हो गये थे। इसलिये महाभारत में कही भी 4 दाँत वाले हाथीयों का सन्दर्भ ही नही है। लेकिन, जैसी हमारी मान्यता है कि द्वापर युग के अन्त में 5240 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, तदनुरूप श्री कृष्ण की द्वारिका के पुरातात्विक अवशेष आज समुद्र में 120 फीट नीचे जल में इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनेग्राफी ने खोज लिये हैं। वे रेडियो कार्बन काल निर्धारण प्रक्रिया में 5000 वर्ष पुराने सिद्ध हुये हैं। उनमें प्राचीन द्वारिका की समुद्र से रक्षार्थ बनायी 30 फीट चौड़ी शहरकोट (नगररक्षा प्राचीर) के अवशेष और उस समय के भवनों, बर्तनों आदि के महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं, जो 5000 वर्ष पुराने सिद्ध हुये हैं। इसके अतिरिक्त वहाँ खम्भात में 7500 वर्ष प्राचीन बन्दरगाह के भी अवशेष मिले हैं, जिनमें जहाजों के लिये 150 से अधिक लंगर, बन्दरगाह की जेटी आदि प्रमुख हैं।

आज हमारे प्राचीन शास्त्र, वाल्मिकी रामायण में वर्णित 10 लाख वर्ष प्राचीन चार दाँत वाले हाथियों के वर्णनों से लेकर कोडूमनाल तक के औद्योगिक अवशेषों के अध्ययन साथ–साथ कोडूमनाल की तमिल ब्राह्मी लिपि से लेकर सिन्धुघाटी सभ्यता में मिली लिपि और दक्षिण अमेरिका में पेरू, चिली व बोलिविया के प्राचीन शिलालेखों की लिपि में यत्किंचित साम्यता के जो प्रारम्भिक अध्ययन हुये हैं उन्हें भी आगे बढ़ाने की आवश्यकता हैं।

पुरातात्विक अवशेषों की दृष्टि से अभी तमिलनाडू में कोडूमनाल में जिस 2500 वर्ष प्राचीन औद्योगिक नगर के पुरातात्विक अवशेष मिले हैं, वहाँ तो उच्च गुणवत्ता का लोहा व स्पात बनाने के उद्योगों, वस्त्रोद्योग व रत्न प्रविधेंयन आदि के महानुमाप उत्पादन के प्रचुर प्रमाण मिले हैं। वहाँ पर पश्चिम के रोम (इटली) व मिश्र के और पूर्व में थाइलैण्ड के सिक्के भी मिले हैं। अर्थात ढ़ाई से तीन हजार वर्ष पूर्व हमारा व्यापार वहाँ तक फैला हुआ था। वहाँ उत्तर भारत व दक्षिण भारत के नामों के संयुक्त लेख भी मिले हैं, वे आर्य–द्रविड़ विभाजन को निर्मूल सिद्ध करते हैं। आज जिन यूरो विट्रीफाइड टाइलों का विकास हम 21 वीं सदी में यूरोप में हुआ मानते हैं, वैसे स्पात उत्पादन के 2500 वर्ष पुराने विट्रीफाइड क्रुसिबल (कड़ाह) भी कोडूमनाल में मिले हैं। इनके साथ ही वहाँ पद्मासन की अवस्था में मिले प्राचीन 2500 वर्ष पुराने नर कंकाल उस काल में योग के प्रचुर चलन का भी प्रमाण देते हैं। आज हमारे प्राचीन शास्त्र, वाल्मिकी रामायण में वर्णित 10 लाख वर्ष प्राचीन चार दाँत वाले हाथियों के वर्णनों से लेकर कोडूमनाल तक के औद्योगिक अवशेषों के अध्ययन साथ–साथ कोडूमनाल की तमिल ब्राह्मी लिपि से लेकर सिन्धुघाटी सभ्यता में मिली लिपि और दक्षिण अमेरिका में पेरू, चिली व बोलिविया के प्राचीन शिलालेखों की लिपि में यत्किंचित साम्यता के जो प्रारम्भिक अध्ययन हुये हैं उन्हें भी आगे बढ़ाने की आवश्यकता हैं। इनसें हम वैदिक, पौराणिक, रामायण कालीन, महाभारत कालीन और उसके परवर्ती कालीन इतिहास पर अधिक प्रकाश डाल सकेंगे। ढ़ाई हजार वर्ष पुराने कोडूमनाल की तमिल ब्राह्मी लिपि व सिन्धु घाटी की 5000 वर्ष पुरानी लिपि में सम्बन्ध तो,

महाभारत काल से हमारी सभ्यता की निरन्तरता को भी प्रतिपादित करेगा।

पुनः हिन्दू काल गणना की वैज्ञानिकता पर आते हुये यदि मासों पर विचार करें तो चान्द्र मासों के साथ–साथ हमारे प्राचीन ऋषियों ने राशियों के नाम पर सौर मासों यथा संक्रान्ति से संक्रान्ति पर्यन्त राशि, अंश, कला व विकला में सौर मास व मास के दिनक्रम के अन्तर्गत 24–24 मिनट की घटियों तक के समय तक का अंकन एक साथ करने का की जो परम्परा विकसित की थी वह आज की आंग्ल दिनाक से भी अधिक व्यवस्थित व सूक्ष्म पद्धति रही है। यह अंकन आज भी पंचागों व जन्म पत्रिकाओं में महादशा व अन्तर्दशा के आरम्भ व समाप्ति काल को इगित करने हेतु किया जाता है। पुनः इन सौर मासों से चान्द्र मासों का सन्तुलन करने के साथ–साथ करोड़ों वर्ष बाद भी चान्द्र मासों का ऋतु चक्र से कुसमायोजन या पृथक्करण नहीं हो जाये, इस हेतु संक्रान्ति रहित मास को 'अधिक–मास' की संज्ञा देकर प्रति तीन वर्ष में एक अधिक मास का प्रावधान कर दिया। इससे हमारे सभी पर्व व त्यौहार एवं वर्षों का प्रारम्भ करोड़ों वर्षों से सदैव उसी ऋतु में होता रहा है व आगे भी होता रहेगा। अरब हिजरी वर्ष मान भी 354 दिन का ही होने से प्रति तीन वर्ष में हिजरी नववर्ष व सभी त्यौहार लगभग, एक माह आगे बढ़ जाते हैं और 9 वर्ष में एक ऋतु से दूसरी ऋतु में चले जाते हैं। इस प्रकार 1393 सौर वर्षों में हिजरी वर्ष 1435 आ गया है।

पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा करती है, उसकी सटीक परिभ्रमण गति को भी पृथ्वी की दैनिन्दिन गति के रूप में आर्य भट्ट ने 2000 वर्ष पूर्व आर्य भट्टीय में दे दिया था। अर्थात प्राचीन काल से ही भारतीयों को यह ज्ञान था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। पृथ्वी की गति के सम्बन्ध में ऐलरेय ब्राह्मण में भी लिखा है कि सूर्य न उदित होता है और न अस्त होता है। सूर्य पृथ्वी के एक भाग को आलोकित करता है, तब दूसरे में व जब दूसरे को आलोकित करता है, तब पहले में अन्धकार होता हैं। यही नहीं पुराणों में वर्णित प्रमुख पाँच विषयों सर्ग (सृष्टि) प्रति सर्ग (प्रलय) आदि में सर्ग या सृष्टि खण्ड में यह भी वर्णन आता है कि सूर्य भी एक महा सूर्य की परिक्रमा 49 हजार योजन प्रति–घटी की गति से कर रहा है। आधुनिक खगोलवेत्ताओं के अनुसार, सूर्य हमारी इस आकाश गंगा में एक अति शाक्तिशाली कृष्ण विवर (Super massive black hole) की लगभग 7.45 लाख किमी. प्रति घण्टा की गति से परिक्रमा कर रहा है और 21 करोड़ 60 लाख वर्ष में वह उसकी एक परिक्रमा पूरी करता है। इतनी अवधि में 50 चतुर्युगियाँ व्यतीत हो जाती हैं। हमारी पौराणिक काल गणनाओं के अनुसार 43.20 लाख वर्ष में एक चतुर्युगी पूरी होती है, जिसमें 4.32 लाख वर्ष का कलियुग, 8.64 लाख वर्ष का द्वापर, 12.96 लाख वर्ष का त्रेता और 17.28 लाख वर्ष का सतयुग होता हैं। इकहत्तर चतुर्युगियों का एक मन्वन्तर और 14 मन्वन्तर अर्थात 1000 चतुर्युगियों का ब्रह्मा जी का एक दिन, ऐसे 360 दिन का ब्रह्मा जी का एक वर्ष व 100 वर्ष की एक ब्रह्मा जी की आयु होती है। एक ब्रह्मा के बाद दूसरे ब्रह्मा जन्म लेते है व सृष्टिक्रम चलता रहता है। इस क्रम में हमारी आकाशगंगा की, इस सृष्टि के ब्रह्माजी के 50 वें वर्ष के श्वेतवाराह कल्प के वैवस्वत मन्वन्तर का 28 वां कलियुग चल रहा है। तदानुसार हमारी इस आकाशगंगा की वर्तमान सृष्टि का यह 195,58,85,115 वाँ वर्ष पूर्ण हो गया है। हमारे पुराणों के अनुसार हमारी इस सृष्टि से युक्त यह जो आकाश गंगा अर्थात तारा मण्डल हमें दिखायी देता है वैसे असंख्य तारा मण्डल या आकाश–गंगायें अनन्त ब्रह्माण्ड में विस्तीर्ण हैं। देवी भागवत में आद्या शाक्ति द्वारा त्रिदेवों को या रामायण में भगवान राम द्वारा काकभुशुण्डि को मन की गति से भ्रमण कराते हुये एक के बाद एक जिन आकाश गंगाओं का कहीं अन्त नहीं होने के दिग्दर्शन का वर्णन किया गया है। इन वृत्तान्तों की अब वैज्ञानिक पुष्टि हो रही हैं कि ब्रह्माण्ड में 100 अरब से अधिक आकाशगंगायें हैं, एक आकाश गंगा का विस्तार लगभग 1,00,000 प्रकाश वर्ष है। दो आकाश गंगाओं के बीच औसत दूरी 25 लाख प्रकाश वर्ष है। आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्माण्ड और भी अनन्त हो सकता है अभी 46 अरब प्रकाश वर्ष पर्यन्त आकाश गंगाओं के विस्तार के प्रमाण मिल चुके हैं। प्रकाश 1.86 मील प्रति सेकण्ड की गति से एक वर्ष में 60 खरब मील तय करता हैं। ऐसे 60 खरब मील का एक प्रकाश वर्ष और ऐसे 46 अरब प्रकाश वर्ष पर्यन्त ब्रह्माण्ड के विस्तार के प्रमाण से अन्त रहित (नेति=न+इति) ब्रह्माण्ड में अनन्त आकाश गंगाओं का पौराणिक वर्णन हिन्दु काल गणनाओं एवं ब्रह्मण्ड के विवरणों की पूर्ण वैज्ञानिकता को सिद्ध करता है। ❑

पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा करती है, उसकी सटीक परिभ्रमण गति को भी पृथ्वी की दैनिन्दिन गति के रूप में आर्य भट्ट ने 2000 वर्ष पूर्व आर्य भट्टीय में दे दिया था। अर्थात प्राचीन काल से ही भारतीयों को यह ज्ञान था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है।

समाचार परिक्रमा

महंगाई-भ्रष्टाचार-कालाधन और विकास मुद्दा

देश में 16वीं लोकसभा का चुनाव शुरू हो गया है सभी पार्टियां अपने–अपने भाषणों में जनता को रीझा रही है परंतु देखा जाए तो आज सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई–भ्रष्टाचार और कालाधन है। भाजपा ने अपने 42 पृष्ठों के चुनावी घोषणा पत्र में साफ कर दिया है। भाजपा सरकार बनीं तो इन मद्दों पर सर्वप्रथम कार्य किया जाएगा। घोषणापत्र में रोजगार की कमी व अल्पसंख्यकों पर भी ध्यान दिया है। इसके अतिरिक्त केन्द्र व राज्य सरकारों की सहभागिता जो विकास के केन्द्रीय एजेंडा पर भी जोर दिया है। घोषणापत्र में बुनियादी ढ़ाचे के विकास में डायमंड क्वाड्रीलेटरल हाई स्पीड कॉरिडोर परियोजा को खास तरजीह दी है। इसके अतिरिक्त सस्ते घर और 100 नए शहर बनाए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय का पुनर्गठन किया जाएगा, हर राज्य में एम्स जैसा संस्थान बनेगा और मदरसों का आधुनिकीकरण होगा। ❑

भारतीय प्रबंधकों पर दुनिया का भरोसा

एक तरफ देश की जनता भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है तो दूसरी ओर दुनिया में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां भारतीयों ने अपनी क्षमता का लोहा न मनवाया हो। अंतरीक्ष से लेकर पेय पदार्थ के कारोबार तक हर जगह भारतीय प्रबंधकों और कार्यकारियों की प्रतिभा को दुनिया ने स्वीकार किया है। अभी हाल ही में जानी मानी कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी डेल इंक ने बड़ी संख्या में भारतीय प्रबंधकों को नियुक्त करना चाहती है जिससे वह अपना कारोबार बढ़ा सके। पिछले दिनों माइक्रोसाफ्ट ने सत्या नाडेल को कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया। दुनियाभर में बड़ी कंपनियों के शीर्ष पदों पर कुछ भारतीयों के नाम हैं – सत्या नाडेला (माइक्रोसाफ्ट), इंद्रा नूयी (पेप्सिको), अंशु जैन (ड्यूश बैंक), अजय बंगा (मास्टरकार्ड), राकेश सचदेव (सिग्मा), दिनेश सी पालीवाल (हरमन इंटरनेशनल), राकेश कपूर (रेककिट बेकिसर) आदि। ❑

आर्थिक विकास दर 5.4 फीसदी

अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष द्वारा जारी विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट में भारत की आर्थिक वृद्धि दर इस साल बढ़कर 5.4 फीसदी पर पहुंच जाएगी जो पिछले वर्ष 4.4 फीसदी रही थी। वैश्विक स्तर पर कुछ बेहतर वृद्धि दर, निर्यात प्रतिस्पर्धा में सुधार और हाल ही में मंजूर निवेश परियोजनाओं के क्रियान्वयन से भारत की आर्थिक वृद्धि दर में वृद्धि होगी। ❑

कारोबारी भरोसा बढ़ा

इस वर्ष की दूसरी तिमाही में व्यापार में इजाफा हुआ है। आर्थिक अनिश्चितता के बावजूद भारतीय कंपनियों के रूख में सकारात्मक बदलाव का असर हुआ है। डन एंड ब्राडस्ट्रीट की रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की है। इंडेक्स आलोच्य तिमाही में 154.5 रहा जो वर्ष 2013 की दूसरी तिमाही की तुलना में 9.1 प्रतिशत की वृद्धि दिखाता है। देखा जाए यह मानकों पर आधारित है जिनमें शुद्ध बिक्री, शुद्ध लाभ, बिक्री कीमतें और नए ऑर्डर शामिल है। ❑

आबादी बढ़ी नहीं बढ़े प्रतिनिधि

16वीं लोकसभा चुनाव में आबादी के अनुपात में संसद में भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों की संख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। जहां 1951 के लोकसभा चुनाव में प्रत्येक सांसद 3.5 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते थे वहीं अब 16वीं लोकसभा में प्रत्येक सांसद करीब 15.5 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेंगे।

सन् 1951 में देश में कुल 17.3 करोड़ मतदाता पंजीकृत थे और अब वर्ष 2014 के चुनाव में करीब 83.9 करोड़ मतदाता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे।

1951 के आम चुनाव में 489 सीटों के लिए मतदान हुआ। फिर 1991 में 543 सीटों के लिए मतदान में कुल मतदाताओं की संख्या 49.8 करोड़ थी। वर्ष 2009 में 543 सीटों के लिए हुए मतदान में कुल मतदाताओं की संख्या 71.7 करोड़ हो गई और प्रति सांसद औसत मतदाताओं की संख्या 13.2 लाख थी।

अब 16वीं लोकसभा चुनाव में 543 सीटों के लिए होने वाले चुनाव में 83.9 करोड़ मतदाता है और प्रति सांसद औसत मतदाताओं की संख्या बढ़कर 15.5 लाख हो गई है।

रैनबैक्सी को खरीदेगी सन फर्मास्युटिकल्स

सन फर्मास्युटिकल्स ने घोषणा की है कि वह 4 अरब डॉलर के सौदे में रैनबैकसी लैबोरेटरीज की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिकारी कर रही है। रैनबैक्सी लैबोरेटरीज को खरीद कर सन फार्मा विशेष जेनेरिक दवा के क्षेत्र में दुनिया की पांचवीं और देश की सबसे बड़ी जेनेरिक दवा कंपनी बन जाएगी। ❑

जलवायु परिवर्तन से भारत में बढ़ेगी घटनाएं

इंटरगवमेंटल पैनल ऑन क्लाईमेंट चेंज (आईपीसीसी) की रिपोर्ट के अनुसार आने वाले सालों में चीन–भारत समेत एशियाई देशों में जलवायु परिवर्तन के घातक नतीजे सामने आ सकते हैं। आईपीसीसी ने अपनी पांचवी रिपार्ट में एशियाई देशों को तीन खतरों से आगाह किया है। रपट में कहा गया है कि एशियाई देशों के इलाकों में तेजी से तापमान बढ़ेगा, जिसके चलते गर्मी से लोगों की जान भी जा सकती है। इसके अलावा गर्मी बढ़ने से एशियाई देशों में मौजूद ग्लेशियरों का पिघलना तेज हो जाएगा जिसके फलस्वरूप नदियों और समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा। ऐसे में इन देशों में बाढ़ का संकट भी पैदा होगा। साथ ही एशियाई देशों में फसलों के नुकसान और बुनियादी ढांचे को भी क्षति पहुंचेगी।

आईपीसीसी के चेयरमैन डॉ. आर. के.पचौरी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए दुनिया के पास अभी भी मौका है। ऐसे में ठोस उपाय की जरूरत है।

ग्रीनपीस की कार्यकर्ता अर्पणा उड़प्पा के अनुसार यह स्पष्ट है कि कोयल और उच्च कार्बन उत्सर्जन से भारत के विकास और अर्थव्यवस्था पर धीरे–धीरे खराब प्रभाव पड़ेगा और देश के जीवन स्तर सुधारने में प्राप्त उपलब्धियां नकार दी जाएंगी और देश में आने वाली नई सरकार इस खतरे से बेखबर नहीं हो सकती। ❑

प्रदूषण और खाद से खराब हो रही हैं सब्जियां

हाल ही में एम्स के आरपी सेंटर ने दक्षिण और उत्तर भारत की सब्जियों की पौष्टिक स्तर की जांच की है। जिसमें उन्होंने पाया कि दक्षिण भारतीय उत्तर भारतीय की अपेक्षा अधिक पौष्टिक सब्जियां खा रहे हैं। जांच के अनुसार उत्तर भारत की सब्जियां की गुणवत्ता में कमी आने का कारण प्रदूषण का स्तर और केमिकल है। गुणवत्ता जानने के लिए आरपी सेंटर ने दिल्ली के आजादपुर फल–सब्जी और दक्षिण भारत में चेन्नई के प्रमुख सब्जी मंडियों से 25 फल और 73 सब्जियों के सैंपल लिए। क्रोमेटोग्राफिक तकनीक के जरिए सब्जी और फलों के पोषक तत्वों की जांच की गई। जिसमें पाया गया कि दक्षिण भारत की 11 प्रमुख सब्जियों में उत्तर भारत की अपेक्षा पोषक तत्वों का स्तर बेहतर है। सब्जियों की जांच के दौरान खेती की जमीन का इस्तेमाल किया गया। डॉ. राजवर्धन आजाद के नेतृत्व में किए गए अध्ययन में पाया गया कि उत्तर भारत में वातावरण में पैदा की गई सब्जियों में कैरोटेनॉयड और अन्य तत्वों का स्तर कम था, जबकि दक्षिण भारत में इसका स्तर बेहतर देखा गया। ❑

आने वाले दिनों में ज्यादा नौकरियों के अवसर

चुनावी माहौल में सरकार बदलने की देश में लहर चल पड़ी है। जिसका परिणाम है कि आने वाले दिनों में कई कंपनियां देश के हालत बदलने पर अपने यहां ज्यादा नौकरियों के अवसर देंगे। नौकरी डॉट कॉम द्वारा किए गए एक सर्वे के अनुसार देशभर में 800 से अधिक कंपनियों के बीच एक सर्वे करावाया गया। जिसमें करीब 64 प्रतिशत नियोक्ताओं ने इस साल नए रोजगार सृजन का संकेत दिया। सर्वे में सबसे ज्यादा नौकरियां फार्मा और आईटीक्षेत्र में आएंगी। ❑

लांझू शहर (चीन) का पेयजल हुआ जहरीला

चीन में अंधाधुंध विकास की अंधी दौड़ में पर्यावरण को नजरंअदाज किए जाने का खामियाजा अब सामने आ रहा है। चीन के एक शहर लांझू में पानी इतना प्रदूषित हो गया है कि बीते शुक्रवार को वहां के लोगों को अपनी प्यास बुझाने के लिए बोतलबंद पानी खरीदना पड़ा। चीन सरकार के मुताबिक पानी में बेनजीन की मात्रा सामान्य स्तर से 20 गुना अधिक पाई गई। बेनजीन को कैंसर का कारक माना जाता है। यह स्थिति तब हुई है जब चीन की नई सरकार ने अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में पर्यावरण को रखा है। एक आंकड़ों के अनुसार चीन के कई हिस्सों में 33 लाख हेक्टेयर जमीन प्रदूषण की वजह से खेती के लायक नहीं है। आज बीजिंग, शंघाई, ग्वांगझो जैसे शहरों में प्रदूषण के उच्च स्तर की वजह से लोग कई बीमारियों से ग्रस्त हैं। ❑

कर्ज के बोझ तले दबा युवा वर्ग

वर्तमान समय में देश की युवा पीढ़ी कर्ज के बोझ तले दबती चली जा रही है। साख सूचना उपलब्ध कराने वाली सिबिल की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले पांच साल के दौरान बैंकों से ऋण मांगने वाले लोगों में 30 वर्ष से कम आयु के लोगों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। रिपोर्ट में कहा का है कि वर्ष 2008 में ऋण मांगने वालों में 30 वर्ष से कम आयु के लोगों का प्रतिशत महज सात था, अब यह बढ़कर 25 प्रतिशत से अधिक हो गया है। संयोग से युवाओं के बीच ऋण लेने में रुचि ऐसे समय में देखने को मिली रही है जब लोग आर्थिक वृद्धि दर में गिरावट के चलते आर्थिक मोर्चे पर नरमी की शिकायत कर रहे हैं। ❑

रपट

बलिदान दिवस पर शहीदों की याद में दिलाया गया संकल्प

तीनों शहीदों की याद में छपे पोस्टर तथा दैनिक जीवन में प्रतिदिन पांच स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करने और 100 प्रतिशत मतदान करने का संकल्प लिया गया।

23 मार्च 2014 (जालोर) स्वदेशी जागरण मंच द्वारा भगतसिंह, राजगुरू, सुखदेव के बलिदान दिवस के दिन स्थानीय रामदेवजी मंदिर भारत माता चौक, तिलक द्वार के अंदर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में स्वदेशी उत्पादो का उपयोग करने व मतदान करने का संकल्प लिया गया और शहर के विभिन्न स्थानों पर संकल्प पत्र भी भरवाया गया। मंच के जिला सह संयोजक दीपक श्रीमाली ने बताया कि मंच की जोधपुर प्रांत कार्यकारिणी द्वारा तय किए गए कार्यक्रम के तहत तीनों शहीदों की याद में छपे पोस्टर तथा दैनिक जीवन में प्रतिदिन पांच स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करने और 100 प्रतिशत मतदान करने का संकल्प लिया गया। इसके साथ ही शहर के गांधी चौक, सुभाष मार्केट, हॉस्पीटल चौराहा, आहोर चौराहा, कालेज चौराहा इत्यादि स्थानों पर आमजनों तथा व्यापारियों तथा विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों को स्वदेशी उत्पादों की जानकारी के साथ ही संकल्प पत्र भी भरवाया गया ।

कार्यक्रम में श्री ईश्वरलाल शर्मा, संरक्षक, कर्मचारी महासंघ, जालोर ने स्वदेशी उत्पादों के उपयोग का संकल्प लिया तथा मंच से आम लोगो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जोडने की बात कही। रेलवे अधीक्षक श्री गंगासिह सोलंकी तथा रेलवे कर्मचारियों द्वारा इसकी सराहना की गई तथा कहा गया कि स्वदेशी उत्पादों को बढ़ाने तथा चीनी उत्पादों को बाजार से हटाने के प्रयास को दूसरे लोगो तक पहुंचाने के देशहितार्थ कार्य को आगे बढाया जाएगा।

कार्यक्रम में श्री दलपतसिंह आर्य, जिलाध्यक्ष कर्मचारी महासंघ एवं आर्य वीर दल, जालोर द्वारा स्वदेशी मंच के इस कार्य को अच्छा प्रयास बताया और तीनों शहीदों के जीवन पर प्रकाश डालते हुए स्वदेशी व महर्षि दयानंद सरस्वती जी के आदर्श समय–समय आमजनों तक पहुँचाया जाएगा। मंच के प्रचारक श्री प्रमोद कुमार आर्य द्वारा प्रत्येक बैठक में नये कार्यकर्ताओं को जोड़ने तथा उत्प्रेरक कार्यों को जिले के ग्रामीण स्तर तक बढाने हेतु विस्तृत कार्ययोजना के बारे में बताया।

श्री अशोक कुमार खिमाणी, मंच प्रचारक द्वारा बलिदान दिवस पर संकल्प पत्र भरवाने हेतु टीम का गठन कर उनका नेतृत्व किया। बैठक में श्री अनिल त्रिवेदी, सुरेश कुमार प्रजापत नें अपने विचार भी प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में प्रिसं शर्मा, श्रवण चौधरी, रावत परमार, रजत शर्मा, हर्षन ओसवाल, जितेन्द्र सोनी, करण बोराणा, कल्पेश शर्मा, दिनेश कंसारा, राहुल सोनी के अलावा बडी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

आज निरंकुश एवं विस्तारवादी तथा आर्थिक व सामरिक नुकसान पहुंचाने वाले चीन के बहिष्कार का संकल्प लिया जाना बहुत ही आवश्यक है - कैलाश भंसाली

23 मार्च, 2014 (जोधपुर) शहीदों ने जब अपने हित को तिलांजली देकर राष्ट्रहित को सर्वोपरी रखा उनके गौरवमयी निर्णय से ही आज भारत माता के इन सपूतों की हम याद कर रहे है आज के माहौल में इन त्रिमूर्ति द्वारा दिए गए संदेश हमारे लिए ज्यादा प्रासंगिक बच गए है। मैं आह्वान करती हूँ कि राष्ट्रहित में चितंन कर हमें शहिद दिवस पर संकल्प लेना चाहिए कि हम राष्ट्रहित को ध्यान में रखकर शत प्रतिशत मतदान मैं सहभागी बनें। यह विचार सूरसागर विधायिका सूर्यकान्ता व्यास ने दीपदान कार्यक्रम के दौरान कहे।

भारत की सीमा पर चीन द्वारा नित रोज नये प्रकारों से दबाव बनाया जा रहा है। हमारे सैनिकों को डरा–धमका कर जब चाहे सीमा में अतिक्रमण कर लिया जाता है। ऐसे में आज शहीद दिवस पर ऐसे निरंकुश एवं विस्तारवादी तथा आर्थिक व सामरिक नुकसान पहुंचाने वाले चीन के बहिष्कार का संकल्प लिया जाना बहुत ही आवश्यक है। स्वदेशी जागरण मंच द्वारा शहीद दिवस पर चीन में निर्मित सामान का बहिष्कार करने का संकल्प लिया गया। वह वास्तविक रूप से हमें हमारे दैनिक जीवन में जरूर अपनाना

होगा। उपरोक्त विचार शहर विधायक श्री कैलाश भंसाली ने रखें। वहीं लघु उद्योग भारती के अखिल भारतीय कोष प्रमुख घनश्याम ओझा ने आज के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए शत–प्रतिशत मतदान हेतु उपस्थित जन समूह को संकल्प दिलाया। जो लोकतंत्र को अपने पराकाष्टा पर पहुंचाने के लिए तथा भारत को गौरवमय बनाने के लिए नितांत आवश्यक है।

स्वदेशी जागरण मंच जोधपुर की ओर से दूसरा महत्वपूर्ण कार्यक्रम शाम को 7 बजे जालोरी गेट चौराहे पर किया गया। तीनों शहीदों की तस्वीरों पर माल्यार्पण किया गया तथा अखण्ड भारत का नक्शा बनाकर उन पर 1100 दीप प्रज्जवलित किये। इस कार्यक्रम का शुभारंभ सूरसागर विधायिका श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास एवं शहर विधायक श्री कैलाश भंसाली ने किया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा कार्यकर्ता दीपक व्यास, रामप्रकाश चौधरी, महेन्द्र मेघवाल, संदीप काबरा, डॉ. अखिलेश शर्मा, गोपाल सिंह भाटी सहित अनेक कार्यकर्ताओं ने तीनों शहीदों की तस्वीरों पर पुष्पाजंलि एवं दीप प्रज्वलित कर इन्हें श्रद्धांजलि प्रदान की। इस दौरान आने जाने वाले सभी स्वदेशी प्रेमियों से स्वदेशी अपनाने एवं मतदान करने का संकल्प पत्र भी भरवाया गया।

जालोरी गेट पर आयोजित कार्यक्रम से पूर्व स्वदेशी जागरण मंच की ओर से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरू के बलिदान दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वदेशी जागरण मंच के राजस्थान सहसंयोजक धर्मेन्द्र दुबे ने बताया की दोपहर 4 बजे गीता भवन से एक भव्य विशाल रैली निकाली गयी। जिसका घनश्याम जी ओझा ने झण्डे दिखाकर रैली का शुभारम्भ किया। यह रैली स्वदेशी नारों और पत्रकों का वितरण करते हुए सरदारपुरा बी रोड़, गोल बिल्ड़िग आदि स्थानों से होते हुए जालोरी गेट चौराहे पर आकर सम्पन्न हुई। इस रैली के दौरान स्वदेशी सामग्री अपनाने के लिए लोगों को संकल्प दिलाये गये साथ ही 100 प्रतिशत मतदान करने का संदेश भी दिया। इस रैली में रोहिताश पटेल, डॉ. अमित व्यास, विनोद मेहरा, चण्डीदान चारण, लूणाराम सैन, अशोक राजपुरोहित, अशोक वैष्णव, जितेन्द्र, गजेन्द्र, मुकेश, अनिल वर्मा, नितेश, ओमप्रकाश भाटी आदि समस्त कार्यकर्ताओं ने इस रैली में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। ❑

शहीद भगत सिंह-सुखदेव-राजगुरू के बलिदान दिवस पर स्वदेशी रैली

23 मार्च (बीकानेर) शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरू के बलिदान दिवस पर रविवार को स्वदेशी जागरण मंच की महानगर इकाई की ओर से स्वदेशी जागरण यात्रा निकाली गयी।

विश्व हिंदू परिषद के श्री गेवर चंद जोशी ने भारत माता की जयघोष के साथ स्वदेशी जागरण यात्रा को रवाना किया। यह साले की होली से एम.एम.स्कूल, नत्थूसर गेट, बाहर गुवाड़, सदाफते, रत्ताणी व्यासों का चौक होते हुए पुनः साले की होली पहुंची। यात्रा में स्वदेशी जागरण मंच, विश्व हिंदू परिषद और अन्य संगठनों के सैंकड़ों कार्यकर्ताओं ने स्वदेशी के उपयोग का आह्वान किया। इससे पहले साले की होली पर आयोजित कार्यक्रम में भारत माता, अमर शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरू तथा स्वदेशी आंदोलन के प्रणेता राजीव दीक्षित के चित्रों पर

पुष्पाजंलि अर्पित की गई। गेवर चंद जोशी ने युवाओं में स्वदेशी की भावना जागृत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भगत सिंह जैसे महापुरूषों के दिखाए मार्ग का अनुसरण करने को कहा। श्रीराम बिस्सा ने बताया कि स्वदेशी जागरण मंच द्वारा स्वदेशी जागरण अभियान संचालित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत मोहल्लों में जाकर आमजन को स्वदेशी चिकित्सा, शिक्षा, गौ आधारित चिकित्सा तथा स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग से राष्ट्र को होने वाले लाभ के बारे में जागरूक किया जाएगा। आनंद व्यास ने स्वदेशी गीत की सुमधुर प्रस्तुति दी। ❑